केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण
सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com
के लिये विज्ञापन बुक कराये।
विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9450567450
9336715406

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :45 अंक 201 रविवार 11 फरवरी 2024 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

विश्वकर्मा चेतना सम्मेलन 12 को

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा द्वारा आगामी 12 फरवरी सोमवार को दिन में 11 बजे बड़े वन के निकट स्थित एक होटल के सभागार में विश्वकर्मा चेतना सम्मेलन का आयोजन किया गया है।

यह जानकारी देते हुये महासभा के जिलाध्यक्ष बैजनाथ शर्मा ने बताया कि विश्वकर्मा चेतना सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व शिक्षा मंत्री एवं महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम आसरे विश्वकर्मा, विशिष्ट अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री राम प्रसाद चौधरी, समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष एवं सदर विधायक महेन्द्रनाथ यादव, विधायक राजेन्द्र चौधरी, कविन्द्र चौधरी अतुल, महासभा के प्रदेश सचिव हरेश्याम विश्वकर्मा के साथ ही अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे।

ब्लाक परिसर से पेड़ काट ले गये चोर

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। गौर थाने से सटे ब्लॉक परिसर से अज्ञात चोर चार यूकेलिप्टस के पेड़ काटकर उठा ले गए। खंड विकास अधिकारी ने पुलिस को सूचना दी।

तत्कालीन खंड विकास अधिकारी गौर ने 27 जनवरी को गौर पुलिस को अवगत कराया कि बीते 26 जनवरी की रात ब्लॉक परिसर में यूकेलिप्टस के दो सूखे और दो हरे पेड़ अज्ञात चोर काटकर उठा ले गये। ब्लाक स्टोर लिपिक गोरखनाथ ने 27 जनवरी को सूचना दी। तत्काल बीडीओ ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए तहरीर गौर पुलिस को दी है।

फर्नीचर उद्योग का निरीक्षण करेंगे मुख्य सचिव

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र कप्तानगंज के गढहा गौतम विशुनपुर स्थिति 'एक जनपद, एक उत्पाद के तहत स्थापित सिद्धमित्रा फर्नीचर उद्योग को भी देखेंगे।

डीएम बस्ती अंद्रा वामसी ने यहां की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र 12 फरवरी को बस्ती में विभागीय योजनाओं की समीक्षा किया जाना है। मुख्य सचिव द्वारा जनपद में समीक्षा के बाद वशिष्ठ आश्रम निरीक्षण करेंगे। इसके बाद गढहा गौतम में ओडीओपी के तहत सिद्धमित्रा फर्नीचर उद्योग को भी देखेंगे।

डीएम बस्ती अंद्रा वामसी ने बढ़नी स्थित वशिष्ठ आश्रम पहुंचे और तैयारी का जायजा लिया। डीएम ने इसके प्रोपराइटर ईश्वर मिश्र से जानकारी ली। गौरतलब है कि सिद्धमित्रा ने उत्सव ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में दो एमओयू 4.8 करोड और पांच करोड़ लकड़ी उद्योग के हस्ताक्षरित किया है।

कार्यकारिणी गठित

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती।दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश शाखा बस्ती की नवीन कार्यकारिणी का गठन हुआ। कुछ संशोधन के साथ पूर्व में कार्यरत कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के नाम का अनुमोदन सर्वसम्मति से आम सभा की बैठक में किया गया।

लक्ष्मी नारायन सिंह संरक्षक, अशोक सिंह अध्यक्ष, चंद्रमोहन श्रीवास्तव सचिव, मो. नियाज अहमद, मूलचंद्र शर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अरुण मौर्य, राधेश्याम सिंह उपाध्यक्ष, आदर्श श्रीवास्तव, शेष मणि वर्मा संयुक्त सचिव, शरद पांडेय, फरीद अहमद संगठन सचिव, जयप्रकाश सिंह कोषाध्यक्ष, रमेश शुक्ल ऑडिटर, रजवंत सिंह क्रीड़ा सचिव, अवध बिहारी श्रीवास्तव प्रचार सचिव, खुशबू गौतम सांस्कृतिक सचिव व कार्यकारिणी सदस्य के रूप में शिवशंकर शुक्ल, सुनील कुमार द्वितीय, संतबली, शाह आलम, निखिल कुमार, योगेश प्रताप सिंह, आकाश सिंह, आयुष कुमार, रजनीश को चुना गया। मार्गदर्शक के रूप में संकटा प्रसाद द्विवेदी व अशोक सिंह को चुना गया।

काशी–मथुरा में ताले हमारी सरकार ने खुलवाये– योगी

लखनऊ (आभा)। विधानसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए सीएम योगी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि आपको तो मथुरा और काशी जाने में डर लगता था। आपको वोट बैंक छिटक जाने का खतरा था। समाजवादी सरकार ने काशी और मथुरा दोनों जगह ताला लगाया था। हमारी सराकर में दोनों जगह ताले खुलवाए गए हैं। हमने काशी–मथुरा या अयोध्या के विकास के लिए ध्यान नहीं दिया है बल्कि वृंदावन, गोकुल, विंध्यवासिनी, नाथ कारिडोर से लेकर प्रयागराज कुंभ के लिए भी धन का आवंटन किया गया है।

योगी से पहले अखिलेश ने कहा कि राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पर भी सीएम योगी ने जवाब दिया। योगी ने कहा कि हमारे लिए राम राजनीति का नहीं आस्था का मामला है। राजनीति तो आप करते हैं। आपको अयोध्या नहीं जाना है क्योंकि वोट बैंक की राजनीति पर असर पड़ जाएगा। हम लोग मंदिर बनने से पहले भी अयोध्या गए थे, आज भी जा रहे और आगे भी जाएंगे। बजट में धनराशि का आवंटन अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, विंध्यवासिनी कॉरिडोर, नाथ कारिडोर सभी के लिए बजट की व्यवस्था की गई है। एक–एक धर्मस्थल को विकसित करने के लिए बजट में धनराशि दी गई है। प्रयागराज में कुंभ के लिए बजट दी गई है।

रहिमन फाटे दूध को मथे न माखन होय.... जयंत चौधरी को लेकर सीएम योगी ने ऐसे साधा अखिलेश यादव पर निशाना

सीएम योगी ने कहा कि आप (अखिलेश यादव) तो मथुरा वृंदावन के लिए भी कुछ नहीं कर पाए थे। आपको वहां जाने में भी डर लगता था। काशी में समाजवादी पार्टी की सरकार ने ताला बंद किया था। मथुरा की जन्मभूमि में भी पीछे से पार्क में ताला समाजवादी सरकार ने लगवाया था। दोनों तालों को हम लोगों ने खुलवाया है। जन्मभूमि के लिए भी बजट में धनराशि की व्यवस्था की गई है।

दोहे से दिया कविता का जवाब

सीएम योगी ने कहा कि मैं तो बिजनौर गया और रात में भी रुका था। आप तो कभी नहीं रुकेंगे। मुख्यमंत्री रहते आप कभी नोएडा और बिजनौर नहीं गए। आपको डर लगता था कि वहां गए तो कुर्सी छिन जाएगी। शिवपाल कुर्सी हथिया लेंगे। आपको अब चाचा पर फैसला लेना चाहिए, आखिर क्यों उपेक्षित बैठे हुए हैं। योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में कुछ करने की जिजीविषा राज्य के नेतृत्व में नहीं थी।

जमीन के विवाद में बुजुर्ग को पीटकर मार डाला, बेटा, बहन घायल

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

कलवारी (बस्ती)। कलवारी थानाक्षेत्र के गौसैसीपुर डड़वा पुरवा में जमीन के विवाद में दर्जनों लोगों ने धारदार हथियारों से लैस होकर एक परिवार पर हमला कर दिया। हमलावरों ने एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की पीटकर हत्या कर दी और 20 वर्षीय बेटे के पैर के पंजे को धारदार हथियार से काट डाला। इस दौरान बुजुर्ग की 67 वर्षीय बहन को पीटकर अधमरा कर दिया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस से घायलों को सीएचसी बनहरा पहुंचाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने घायल युवक को जिला अस्पताल, फिर बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। सूचना पर पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया, घटना के बाद से गांव में तनाव है। मौके पर एएसपी, सीओ और कई थानों की पुलिस ने पहुंचकर हालात को काबू किया।

पुलिस के मुताबिक शनिवार को दोपहर तकरीबन 1.30 बजे राममिलन चौधरी (70 वर्ष) के घर गांव के ही दलित परिवार के दर्जनों लोग धारदार हथियारों से लैस होकर चढ़ गए। अचानक हुए हमले में राममिलन चौधरी पुत्र बालेदीन चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए। पिता को हमलावरों से बचाने पहुंचे 20 वर्षीय बेटे विशाल और 67 वर्षीय बहन माला देवी पर भी लोगों ने हमला कर दिया। हमले के दौरान विशाल को जमकर पीटा और धारदार हथियार से बाएं पैर के पंजे को काट दिया। गांववालों को जुटता देखकर हमलावर भाग गए।

ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर एएसपी ओपी सिंह, सीओ अशोक मिश्रा, थानाप्रभारी कलवारी भानुप्रताप सिंह, थानाप्रभारी नगर संतोष कुमार, थाना प्रभारी कप्तानगंज दीपक दुबे, थाना प्रभारी दुबौलिया नारायण लाल श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार स्वाति सिंह, नायब तहसीलदार वीरबहादुर सिंह सहित काफी संख्या में पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंच गई। इस बाबत सीओ अशोक कुमार मिश्र ने बताया कि शव को पीएम के लिए भेजा जा रहा है। तहरीर के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।

अयोध्या में रामलला के नहीं इटावा शिव मंदिर पर दर्शन करेंगे सपा विधायक

लखनऊ (आभा)। यूपी में अयोध्या राम मंदिर पर अभी भी सियासत जारी है। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर राम मंदिर दर्शन के निमंत्रण पर किनारा कर लिया है। भाजपा के अयोध्या दर्शन के जवाब में 11 फरवरी को अखिलेश यादव अपने दर्जनों सपा विधायकों के साथ इटावा के केदारेश्वर मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं। रविवार देर शाम सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने विधायकों के साथ में लखनऊ से रवाना होंगे। इटावा में लाइन सफारी के पास केदारेश्वर मंदिर फिलहाल निर्माणधीन है। उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर केदारेश्वर मंदिर बन रहा है।

दरअसल, 11 फरवरी को यूपी के विधायकों को श्रीराम मंदिर में दर्शन को अयोध्या जाने के लिए निमत्रंण दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदन में स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री की ओर से वह विधायकों को अयोध्या चलने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन किसी सदस्य का अयोध्या चलना बाध्यकारी नहीं है। इसके बाद सपा सदस्यों के बयान सामने आए। रामलला दर्शन के निमंत्रण को समाजवादी पार्टी ने ठुकरा दिया है। सपा के महासचिव शिवपाल ने 11 फरवरी को अयोध्या जाने से इनकार कर दिया है। शिवपाल यादव ने कहा कि 11 तारीख को हमारा कोई औचित्य नहीं बनता है वहां जाने का।

इसके बाद समाजवादी पार्टी ने इटावा के केदारेश्वर मंदिर जाने का फैसला लिया है। सपा के मुखिया अपने विधायकों के साथ इटावा के इस शिव मंदिर में 11 फरवरी को दर्शन– पूजन करने का निर्णय लिया है। सपा के सभी विधायक बस से इटावा के लिए रवाना होंगे। मंदिर में दर्शन पूजन के बाद पार्टी के सभी विधायक मंदिर दर्शन के बाद लायन सफारी भी जाएंगे।

यूपी में सुशासन अचानक नहीं आया, करने पड़े कई बड़े रिफॉर्म– योगी आदित्यनाथ

नई दिल्ली (आभा)। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश में सुशासन की स्थापना अचानक नहीं हुई है, बल्कि इसके लिए बड़े स्तर पर रिफॉर्म किए गए। पहले की सरकारों ने जाति, मत–मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर समाज को बांटने और ठगने का कार्य किया, मगर आज विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबों को आत्मनिर्भर बनाया गया है। प्रदेश में पहले भी पोटेंशियल था, मगर तब की सरकारों ने इसका बेहतर उपयोग नहीं किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित ₹सुशासन दिवस 2024₹ कार्यक्रम में बोलते हुए ये बातें कहीं। सीएम योगी ने कहा कि सुशासन महोत्सव 2024 प्रधानमंत्री के विकसित भारत के विजन को हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। बीते 10 साल में पूरी दुनिया नये भारत का दर्शन कर रही है। भारत आज दुनिया को समर और विषम परिस्थितियों में नेतृत्व देने का सामर्थ्य रखता है। देश के अंदर सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना है। सीएम योगी ने कहा कि जैम ट्रिनिटी (जनधन, आधार और मोबाइल) के माध्यम से जहां भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगा है तो वहीं डीबीटी के माध्यम से अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक शासन की योजनाएं और सेवाएं पहुंचाने का कार्य हुआ है।

सीएम ने बताया कि आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हुई है। पहले हम भारतवासियों को कहा जाता था कि हमारा जो कुछ भी ज्ञान है वो पोंगापंथी है। हमारी परंपराओं को लांछित किया जाता था। आज दुनिया के 193 देश 21 जून की तिथि को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप मनाती है। भारत की इस ऋषि परंपरा से जुड़कर पूरी दुनिया ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से हमारी परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है। ये सब प्रधानमंत्री मोदी के कारण संभव हो सका है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अंदर चल रही तमाम विकास परियोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने यूपी में इन्फ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में हुए कार्यों को गिनाया। साथ ही प्रदेश में सुदृढ़ हुई कानून व्यवस्था जैसी उपलब्धियों के बारे में भी बताया। सीएम योगी ने कहा कि केवल योजना बनाने से सुशासन नहीं आता, बल्कि योजनाओं के क्रियान्वयन का तरीका और उसकी मॉनीटरिंग बहुत जरूरी है। सरकार ने टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उपयोग किया है। सरकार ने बिना भेदभाव के कानून का राज स्थापित किया है। प्रदेश में नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी है। एमएसएमई क्लस्टर को मजबूती प्रदान की गई। ओडीओपी योजना लाकर परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित किया गया। मुख्यमंत्री ने सीएम इंटर्नशिप स्कीम, प्लेज पार्क स्कीम की भी चर्चा की। सीएम ने प्रदेश में बेहतर हुई कनेक्टिविटी की चर्चा करते हुए बताया कि जल्द ही यूपी 21 एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। यूपी में सर्वाधिक एक्सप्रेस वे हैं।

मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर प्रदेश में नये उद्यमियों के लिए लाई गई पांच लाख तक के ब्याज मुक्त ऋण की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का फोकस प्रतिवर्ष एक लाख नये युवा उद्यमियों को तैयार करने पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में सफलता पूर्वक कोरोना महामारी का सामना किया और किसी को बेरोजगार नहीं होने दिया गया। यूपी आज बीमारू राज्य से ऊपर उठकर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन चुका है। आज प्रदेश में उद्योगिक निवेश का बेहतर माहौल है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 40 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ। इससे 1 करोड़ 30 लाख से अधिक नौजवानों को रोजगार मिलेगा। 19 फरवरी को प्रधानमंत्री की उपस्थिति में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें 10 लाख करोड़ के उद्योगों का भूमिपूजन होने जा रहा है।

पीएम मोदी ने गिनाई कार्यकाल की उपलब्धियां

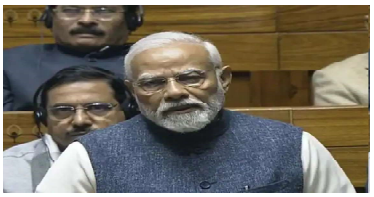

नई दिल्ली (आभा)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वीं लोकसभा के अंतिम सत्र के आखिरी दिन सदन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पांच साल की उपलब्धियां गिनाईं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पिछले पांच साल के दौरान देश किस तरह से रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के दौर से गुजरा है। पीएम मोदी ने कहाकि सबसे अच्छी बात है कि इन चीजों को देश में महसूस भी किया जा सकता है। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने संसद के सदस्यों का स्वागत किया और सदन चलाने के लिए स्पीकर ओम बिरला की तारीफ की।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहाकि ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि रिफॉर्म और परफॉर्म एक साथ देखने को मिले। इसके साथ ही हम अपनी आंखों के सामने ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देख रहे हैं। उन्होंने कहाकि यह सब 17वीं लोकसभा की देन है। पीएम मोदी ने कहाकि प्रजातंत्र की परंपरा में यह बेहद खास दिन है। उन्होंने कहाकि बीते पांच साल में सभी ने अपनी–अपनी क्षमता के मुताबिक देश के विकास में अपना योगदान दिया है। उन्होंने कहाकि पांच साल की वैचारिक यात्रा और देश सेवा में समर्पण के बद फिर से डेडिकेट करने का दिन है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाकि 17वीं लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 97 फीसदी रही। मुझे विश्वास है कि हम 18वीं लोकसभा में शत प्रतिशत की उत्पादकता रहने का संकल्प लेंगे। मोदी का कहना था कि जी–20 शिखर सम्मेलन के दौरान देश के हर राज्य ने भारत के सामर्थ्य और अपने प्रदेश की खूबी विश्व के सामने रखी जिसका असर आज भी है तथा श्पी–20₹ के माध्यम से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया। उन्होंने संसद के नए भवन का निर्माण करवाने का निर्णय लेने का श्रेय लोकसभा अध्यक्ष बिरला को देते हुए कहा कि उसी का परिणाम है कि देश को संसद का नया भवन प्राप्त हुआ।

इमरान खान को 12 मामलों में मिली जमानत

लाहौर (आभा)। पाकिस्तान में आम चुनाव के ऐलान के बीच इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। बीते साल सेना के ठिकानों पर हमले को लेकर उन्हें 12 मामलों में जमानत मिल गई है। इमरान खान के साथ ही उनके साथ विदेश मंत्री रहे शाह महमूद कुरेशी को भी राहत दी गई है। बता दें कि पाकिस्तान के चुनाव में जेल में रहते हुए भी इमरान खान के उम्मीदवारों का प्रदर्शन उम्दा रहा है। इमरान खान के समर्थकों ने निर्दलीय ही चुनाव लड़ा था। वहीं नवाज शरीफ ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पीएमएल–एन और पीपीपी मिलकर सरकार बनाने को सहमत भी हो गए हैं।

बता दें कि बीते साल 9 मई को हुई हिंसा को लेकर इमरान खान समेत पीटीआई के कई अन्य नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। दरअसल इस्लामाबाद में इमरान खान की गिरफ्तारी हो गई थी। इसके बाद उनके समर्थकों ने हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया। इमरान के समर्थक रावलपिंडी में सेना के परिसर में घुस गए और जमकर तोड़फोड़ की। आरोप था कि इमरान खान के जमन पार्क स्थित आवास के बाहर पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी की गई। इसके अलावा लाहौर के पुलिस थाने पर भी हमला किया गया।

हिंसा के बाद इमरान खान के 100 से ज्यादा समर्थकों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं 2022 में इमरान खान की सरकार गिर गई।

विधायक अजय सिंह ने सदन में किया पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भारत रत्न देने की मांग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। हरैया विधायक अजय सिंह ने सदन में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भारत रत्न देने की मांग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, स्वामीनाथन और नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की सराहना करते हुए उन्होने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी भारत रत्न दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की सराहना करते हुए विधायक ने सदन में कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के संकल्प को पूरा करने वाला है। 84 कोसी परिक्रमा के प्रारंभ स्थल जो भगवान श्रीराम का मूल है उसकी शानदार रोड बन रही है। मखौड़ा धाम से अयोध्या धाम तथा मखौड़ा धाम से श्रृंगीनारी के लिए राम अवतरण कॉरिडोर का प्रस्ताव करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। विधायक अजय सिंह ने बताया कि राम मंदिर निर्माण और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवादी सरकार बनाने में बड़ी भूमिका स्व. कल्याण सिंह की रही है। करोड़ों लोगों की आस्था व विश्वास के प्रतीक राम मंदिर निर्माण में कारसेवकों पर गोली चलाने से मना कर यह साबित कर दिया कि कुर्सी और सत्ता से आस्था बड़ी होती है। वे एक लोकप्रिय, ओजस्वी और अनुकरणीय नेता थे इसलिए कल्याण सिंह को भारत रत्न दिया जाना चाहिए।

विधायक महेन्द्रनाथ यादव ने सदन में किया मुण्डेरवा कस्बे में अग्नि शमन केन्द्र स्थापित कराने की मांग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। सदर विधायक महेन्द्रनाथ यादव ने बजट सत्र के दौरान मुण्डेरवा कस्बे में अग्नि शमन केन्द्र स्थापित कराने की मांग किया। सदन में यह मुद्दा उठाते हुये सपा विधायक महेन्द्रनाथ यादव ने कहा कि गर्मी के दिनों में प्रायः मुण्डेरवा क्षेत्र में आग लगने की सर्वाधिक घटनाये सामने आती है और जन धन के साथ ही गेहूं के फसल का भारी नुकसान होता है। जब तक बस्ती से अग्नि शमन के लोग पहुंचते हैं बड़ा नुकसान हो चुका होता है। यदि मुण्डेरवा में अग्नि शमन केन्द्र की स्थापना हो जाय तो प्रति वर्ष गर्मी के मौसम में होने वाली वाली जन धन और फसलों के नुकसान को रोका जा सकता है। स्थानीय नागरिक लगातार अग्निशमन केन्द्र का मुद्दा उनके समक्ष भ्रमण के दौरान उठा रहे हैं।

विधायक महेन्द्रनाथ यादव के सवाल पर सम्बंधित मंत्री ने कहा कि मुण्डेरवा कस्बे में अग्नि शमन केन्द्र स्थापित कराने के लिये परीक्षण के बाद निर्णय लिया जायेगा।

ज्ञात रहे कि बजट सत्र के दौरान सपा विधायक महेन्द्रनाथ यादव शिक्षा मित्रों को स्थायी शिक्षक बनाने, ओ.बी.सी. को नियुक्तियों में आरक्षण का लाभ दिये जाने, महापुरूषों के मूर्तियों की सुरक्षा करने, मूर्तियां खण्डित करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई, बस्ती के बंद पड़ी चीनी मिल पर गन्ना किसानों के 45 करोड़ रूपये बकाये का भुगतान कराकर श्रमिकों का वेतन भुगतान कराने, बस्ती जिला अस्पताल एवं मेडिकल कालेज में हृदय रोग, न्यूरो चिकित्सकों के तैनाती किये जाने, कांदू, कसौधन, साहू समाज के लोगों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने, मेडिकल कालेज मार्ग का चौड़ीकरण किये जाने के साथ ही मुण्डेरवा क्षेत्र के अनेक सड़कों के निर्माण, अधूरे पड़े इंजीनियरिंग कालेज को शुरू कराये जाने का मुद्दा जलजीवन मिशन के तहत पाइप लाइन बिछाने में जो सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं उन्हें पुनं स्थापित कराने आदि का मुद्दा उठा चुके हैं।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 11 फरवरी 2024 रविवार

सम्पादकीय

काशी, मथुरा और राजनीति

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की सराहना करते हुए वाराणसी और मथुरा में हिंदू पक्षों के दावों का समर्थन करके जहां अपने मंतव्य को स्पष्ट किया है, वहीं समाज में आधिकारिक स्तर पर एक विमर्श को भी जन्म दिया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री का यह भाषण अनेक अर्थों में कालजयी है, जिसमें समय परिवर्तन की गूंज भी निहित है। ऐसे भाषण की कल्पना पहले असंभव थी। एक नए उभरते भारत के सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में धर्मस्थलों और मंदिरों के शहरों के प्रति लगाव नई दशा और दिशा का सूचक है। मुख्यमंत्री ने राम मंदिर के निर्माण में बाधा डालने के लिए विपक्षी दलों की भी आलोचना की है और साथ ही, उन पर राजनीतिक लाभ के लिए आक्रमणकारियों का महिमामंडन करने का भी आरोप लगाया है। मंदिर बहुल शहरों के विकास पर ध्यान देना प्रशंसनीय है और इसमें संदेह नहीं कि यह काम पहले भी हो सकता था। धार्मिक महत्व के ज्यादातर शहर बुनियादी सुविधाओं के अभाव और गंदगी से बहुत परेशान रहे हैं। अतः अब अगर इस विषय पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो स्वागतयोग्य है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी आदित्यनाथ राम मंदिर के मुद्दे पर बोलते हुए इशारों–इशारों में मथुरा और काशी का मुद्दा भी छेड़ दिया। उन्होंने वर्तमान राजनैतिक परिदृश्य की तुलना महाभारत से करते हुए कहा कि दुर्योधन से पांडवों ने केवल पांच ग्राम मांगे थे। दुर्योधन वह भी न दे पाया। यही हाल तो अयोध्या, मथुरा और काशी के साथ हुआ। हमने तो केवल तीन जगह मांगी है।

योगी ने कहा, 'अयोध्या की बात होती है तो हमें पांडवों की याद आती है। कृष्ण गए थे दुर्योधन के पास उन्होंने कहा था कि दे दो हमको पांच ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका। यहां तक कि उसने भगवान कृष्ण को बंधक बनाने का प्रयास किया।' योगी ने कहा कि यही तो हुआ था अयोध्या के साथ। यही हुआ था काशी के साथ। यही हुआ था मथुरा के साथ। पांडवों ने भी केवल पांच ग्राम मांगे थे लेकिन यहां कोई समाज, यहां की आस्था केवल तीन के लिए बात कर रही है। वो तीन के लिए भी इसलिए कि वे विशिष्ट स्थल हैं। ईश्वर की अवतरण की धरती हैं। वह सामान्य नहीं है लेकिन एक जिद है। उस जिद में जब राजनैतिक तड़का पड़ने लगता है तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है।

राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में अपने दूसरे कार्यकाल के लगभग मध्य में मुख्यमंत्री ने वाराणसी में ज्ञानवापी और मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान की मुक्ति की ओर साफ संकेत किया है। द्वापर में महाभारत से बचने के लिए श्रीकृष्ण ने कौरव सभा में महाराजा धृतराष्ट्र से पांडवों के लिए पांच गांव मांगे थे, ठीक वैसे ही मुख्यमंत्री ने निवेदन किया कि आज हिंदू समाज आस्था के केवल तीन केंद्र मांग रहा है। आधिकारिक रूप से विधानसभा में की गई यह मांग न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि इसका व्यापक असर हमारे समाज पर आने वाले दिनों में दिखाई पड़ सकता है। वैसे समुदाय विशेष पहले इस तरह की मांग को एकाधिक बार खारिज कर चुका है। जब प्रधानमंत्री पद पर चंद्रशेखर बैठे थे, तब भी और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समय भी यह निवेदन चर्चा में आया था, पर अब तक ऐसे निवेदनों को बहुमत से ठुकराने का इतिहास ही जगह–जगह दर्ज है। तीन भगवान के नाम पर तीन स्थान अगर दे दिए जाते, तो किसी धर्मस्थल को जबरन ढहाने की नौबत शायद न आती। सवाल यह है कि क्या अब समुदाय विशेष में कुछ देने की भावना आएगी? क्या व्यापक समाज में बहुमत के प्रति आदर का भाव आएगा?

राज्यसभा सांसद व राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पुस्तक संस्कृति के चार अध्याय में इशारा किया है कि सद्भाव के लिए बहुसंख्यक समाज यह भूल जाए कि उसके साथ अत्याचार हुआ था और अल्पसंख्यक समुदाय यह भूल जाए कि उसने इस देश पर कभी राज किया था। चूंकि यह सदिच्छा पूरी नहीं हुई है, इसलिए हिन्दुस्तान में सद्भाव की गाड़ी अक्सर पटरी से उतर जाती है। सांप्रदायिकता की बुनियाद पर हमारा बंटवारा भी हो चुका है, मगर अब कतई नहीं। हर समुदाय को तर्क, तथ्य और हालात को समझते हुए आगे बढ़ना होगा। कुछ अच्छी बुनियादी बातों को दिल से लगाए रखने की जरूरत है। अब 6 दिसंबर कभी न लौटे, अदालत और परस्पर संवाद से हल निकले, किसी के हाथों में नफरत की तलवार न आए। एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ते उत्तर प्रदेश की राह में उपद्रव का एक भी अवरोधक न उभरने पाए, ताकि हम अनुभव करें कि रामलला नए भवन में आए हैं, तो राम भाव भी आया है।

पाकिस्तान में चुनाव और सियासी उथल–पुथल

–अभिनव आकाश –

एक समय पर इमरान खान भी पाकिस्तानी सेना के फेवरेट थे। लेकिन फिर कहानी पूरी तरह से बदल सी गई। 2018 के चुनावों से ठीक पहले, नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग–एन इसी तरह सत्ता प्रतिष्ठान के क्रोध का शिकार थी और बाद में सत्ता प्रतिष्ठान के आशीर्वाद से पीटीआई सत्ता में आई थी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ ने लंदन में अपना लगभग पांच साल लंबा निर्वासन जैसे ही समाप्त किया, 10 दिवसीय धार्मिक तीर्थयात्रा के लिए सऊदी अरब पहुंचे, इस 'उमरा' के राजनीतिक रंग ने घड़ी की टिक–टिक तेज कर दी। स्व–घोषित मसीहा इमरान खान एक समय सर्वशक्तिमान रही पाकिस्तान सेना के खिलाफ अपनी जनता की ताकत को खड़ा करते हुए, बेबाकी से राजनीतिक कहानी को फिर से लिखा है। सेना के नए चीफ जनरल असीम मुनीर के नेतृत्व में शीर्ष अधिकारियों द्वारा सीधे तौर पर हस्तक्षेप न करने के निर्णय के बाद सेना बैकडोर मिशन को लगातार जारी रखा है। चुनाव का माहौल हो और इसके परिणामों को लेकर जब भी रिजल्ट से पहले चर्चा होती है तो एक चिरपरिचित श्लाइन नतीजे चौंकाने वाले होंगेश हमेशा सुनने को मिल जाता है। लेकिन ऐसा होता भी प्रतीत हो रहा है। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने चुनावी नतीजों ने सभी को चौंका दिया है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान तहरीक–ए–इंसाफ पार्टी (पीटीआई) से जुड़े 10 से भी ज्यादा उम्मीदवार जीत दर्ज कर पाएंगे। इमरान 23 अगस्त 2023 से जेल में हैं। कई संगीन मामलों में उन्हें सजा हुई। इमरान के चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा उनके कई बड़े नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया। चुनाव से पहले पीटीआई का क्रिकेट बैट वाला सिंबल भी छीन लिया गया। लेकिन फिर भी पीटीआई नेताओं ने निर्दलीय रूप से चुनाव मैदान में उतरते हुए शतक पूरा किया। मिलिट्री इस्टैबलिस्मेंट की फेवरेट मुस्लिम लीग नवाज की इस चुनाव में एकतरफा जीत के सपनों को चकनाचूर कर दिया।

पाकिस्तान के चुनाव में अमूमन वोटिंग वाले दिन ही नतीजे भी आ जाते हैं। लेकिन 8 फरवरी की रात को आने वाले नतीजे आने में देरी हुई। नेटवर्क समस्या का बहाना बनाकर रिजल्ट रोका गया। जब नौ फरवरी की सुबह हुई और नेटवर्क पटरी पर आया तो पीटीआई पिछड़ने लगी। रात आते–आते पीएमएलएन के सबसे बड़े नेता और प्रधानमंत्री पद के दावेदार नवाज शरीफ विजेता हो चुके थे। पीटीआई ने धांधली का आरोप लगाया। पाकिस्तान में चार राज्य हैं– पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान। इनकी विधानसभा को प्रांतीय सभा कहते हैं। इनमें बहुमत हासिल करने वाले नेता मुख्यमंत्री बनते हैं। नेशनल असेंबली संसद का निचला सदन है। इसमें कुल 336 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 169 है। 266 सीटों पर जनता सीधे वोट डालती है। बाकी 70 सीटों पर महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित है। 266 में से जिस पार्टी को जितनी सीटें मिलती हैं उसी अनुमात में सीटों का बंटवारा होता है।

पाकिस्तान का इतिहास ही देखा जाए तो उसमें साफ–साफ नजर आता है कि देश में राजनीतिक पकड़ पार्टियों से ज्यादा पाकिस्तानी सेना की है। अक्सर फैसले में सेना सरकार पर हावी होती नजर आई है या फिर यू कहें कि जब से पाकिस्तान की स्थापना हुई तब से ही सेना पावर में रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और कई नेता इस बात पर हामी भी भरते हैं। इमरान खान के भी यही बोल थे कि पाकिस्तान में सत्ता किसी के पास हो लेकिन ताकत सेना के पास ही रहती है। दखल और रुतबा भी फौज का ही रहता है। अगर कोई इस बात से इनकार कर रहा है तो वो बिल्कुल ही गलत है। ऐसा खुद इमरान खान ने कहा था। विदेशी मामलों के जानकार भी कहते आए हैं कि पाकिस्तान की जनता ये अच्छी तरह से जान गई है कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव असल में हो ही नहीं सकते।

पाकिस्तान की सियासत में सेना का दबदबा इसी कारण है क्योंकि युद्ध में हार के बाद भारत से खतरा बताया जाता है। तख्तापलट का सिलसिला आजादी मिलने के बाद ही शुरू हुआ था। स्कंदर को सपोर्ट करने वाले अयूब खान ने पहले तो पाकिस्तान के संविधान को बर्खास्त करवाया और फिर मार्शल लॉ लागू करवाया। इसे ही सेना का पहला तख्तापलट कहा जाता है। फिर जिया उल हक के तख्तापलट ने तो देश–दुनिया में सुर्खियां बटोरी। लेकिन वक्त के साथ उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान में हालात सुधरेंगे। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट और वो बेपटरी होता गया। पाकिस्तान के आम चुनावों में नवाज शरीफ की जीत के बाद उन्होंने जिस परवेज मुशर्रफ को सेना प्रमुख बनाया उन्होंने ही आगे चलकर मियां नवाज को कुर्सी से उतारा और देश निकाला भी दे दिया।

एक समय पर इमरान खान भी पाकिस्तानी सेना के फेवरेट थे। लेकिन फिर कहानी पूरी तरह से बदल सी गई। 2018 के चुनावों से ठीक पहले, नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग–एन इसी तरह सत्ता प्रतिष्ठान के क्रोध का शिकार थी और बाद में सत्ता प्रतिष्ठान के आशीर्वाद से पीटीआई सत्ता में आई थी। इसके बाद इमरान खान ने तेजी से पाकिस्तानी सेना के साथ करीबी रिश्ते बनाए। अपने प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कश्मीर मुद्दे (अनुच्छेद 370 को निरस्त करने) पर अपने रुख के संदर्भ में सेना के एजेंडे को काफी आगे बढ़ाया। अमेरिका के साथ संबंधों में सुधार किया और कुछ हद तक बढ़े हुए सैन्य खर्च को बनाए रखने के लिए धन जुटाने का प्रबंधन किया। हालाँकि, सैन्य समर्थन के तहत इमरान खान की शक्ति का एकीकरण अल्पकालिक रहा। प्रतिष्ठान के साथ मतभेद पहली बार 2021 में खुलकर सामने आए जब पूर्व सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को इंटर–सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया। खान ने अपनी पसंद के जनरल फैज हमीद के पक्ष में इसका विरोध किया। हालाँकि, बाद में वह कोई बदलाव लाने में असफल रहे। बाद में खान और बाजवा दोनों में विदेश नीति के मुद्दों पर मतभेद होने लगे। इसके अलावा, खान ने विभिन्न राजनीतिक मंचों पर सेना के साथ अपनी निजी चर्चा के बारे में खुलकर बोलना शुरू कर दिया, जिसे शायद सत्ता प्रतिष्ठान ने अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण इमरान खान को जेल में डाल दिया गया।

यह कैसा और किसका लोकतंत्र

–हरि जयसिंह–

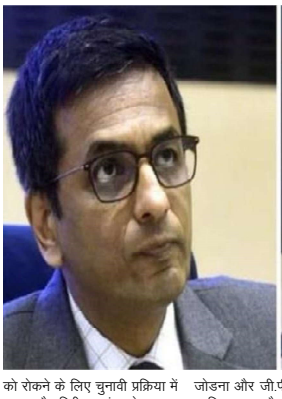

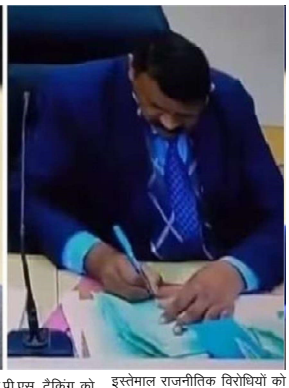

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने हाल ही में चंडीगढ़ चुनाव की घटना की निंदा करते हुए इसे 'लोकतंत्र का मजाक' बताया। इस मामले में, रिटर्निंग ऑफिसर को 'भगौड़े' की तरह ओवरहैड कैमरे पर नजर डालते हुए मतपत्रों के साथ खुलेआम छेड़छाड़ करते हुए देखा गया। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विपक्षी गठबंधन, 'इंडिया' के बीच एक महत्वपूर्ण मुकाबला होने की उम्मीद थी। हालांकि, चुनाव के बाद परेशान करने वाली अनियमितताएं सामने आईं जिससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर संदेह पैदा हो गया।

सोशल मीडिया पर उस समय विवाद खड़ा हो गया जब एक वीडियो में कहा गया कि भाजपा से जुड़े चुनाव अधिकारी ने 8 मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ की होगी, जो अजीब तरह से 'आप' कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में थे। यह रहस्योद्घाटन चुनाव के संचालन और चुनाव अधिकारियों की निष्पक्षता के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। बड़ी संख्या में अमान्य वोट, विशेष रूप से एक पार्टी को असंगत रूप से प्रभावित करने वाले, वोट–गिनती प्रक्रिया की अखंडता पर सवाल उठाते हैं। इसके अतिरिक्त, बाहरी राजनीतिक प्रभाव और सीमित निरीक्षण तंत्र के आरोप स्थिति की जटिलता को बढ़ाते हैं।

इन चिंताओं को दूर करने के प्रयास चल रहे हैं। कानूनी चुनौती ने सुप्रीम कोर्ट को कथित अनियमितताओं की गहन जांच करने के लिए प्रेरित किया है। वीडियो फुटेज और अन्य सामग्रियों की जांच सहित सबूतों की जांच का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या चुनाव की अखंडता से समझौता किया गया था। मुख्य न्यायाधीश ने इसमें शामिल व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया कि 'देश में बड़ी स्थिर शक्ति चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता है', जिसे हमेशा उचित सम्मान के साथ बरकरार रखा जाना चाहिए। आगामी 2024 के भारतीय आम चुनावों को देखते हुए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। यह घटना लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के महत्व की याद दिलाती है।

मीडिया कवरेज और सार्वजनिक चर्चा पारदर्शता को बढ़ावा देने और संपूर्ण और निष्पक्ष जांच की गारंटी के लिए दबाव डालने में महत्वपूर्ण हैं। जांच के निष्कर्षों के आधार पर, भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए चुनावी प्रक्रिया में सुधार और निरीक्षण तंत्र को मजबूत करने की मांग हो सकती है। यह घटना इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ई.वी.एम.) के मुद्दे को सामने लाती है और यह भी बताती है कि उनमें कैसे हेरफेर किया जा सकता है। पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी कन्नन गोपीनाथन और कम्प्यूटर विज्ञान विशेषज्ञ माधव देशपांडे ने हाल ही में महाराष्ट्र में पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारत की मतदान प्रणाली पर चर्चा की।

उन्होंने इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग और नागरिकों के मतदान अधिकारों पर इसके प्रभाव पर चर्चा की। गोपीनाथन ने 2019 में रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में अपने अनुभव के आधार पर ई.वी.एम. की विश्वसनीयता के बारे में चिंता जताई और पारदर्शी चुनावों की आवश्यकता पर बल दिया। देशपांडे ने भारत में ई.वी.एम. में हेरफेर के बारे में चिंताओं को उजागर किया है। उनकी स्पष्ट और सीधी व्याख्याएं इन मुद्दों को सीधे तौर पर समझने के महत्व पर जोर देती हैं। उन्होंने बताया कि हालांकि वाई–फाई, ब्लूटूथ या इंटरनैट कनैक्टिविटी की कमी के कारण ई.वी.एम. को हैक नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनमें हेरफेर का खतरा है। देशपांडे ने बताया कि मतदाता–सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल (वी.वी.पी.ए.टी.) मशीन और नियंत्रण इकाई के माध्यम से मतदान में कैसे हेर–फेर किया जा सकता है।

देशपांडे ने मतदान प्रणाली को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव दिया है, जैसे नियंत्रण इकाइयों और वी.वी.पी.ए.टी. दोनों को एक साथ मतदाता विकल्प भेजना, नियंत्रण और मतपत्र इकाइयों को इलैक्ट्रॉनिक रूप से जोडना और जी.पी.एस. ट्रैकिंग को शामिल करना है। दोनों विशेषज्ञों ने यह सुनिश्चित करने के लिए भारत की मतदान प्रक्रिया में बड़े सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया। चुनावी अखंडता संबंधी चिंताओं के अलावा, प्रमुख राजनेताओं द्वारा सामना की जाने वाली कानूनी परेशानियां भारत में राजनीतिक जवाबदेही और कानून के शासन के बारे में व्यापक सवाल उठाती हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दबाव में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस्तीफा, उसके बाद भूमि अधिग्रहण से संबंधित आरोपों पर उनकी गिरफ्तारी, राजनीतिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार और आपराधिकता की चुनौतियों को उजागर करती है।

ई.डी. द्वारा असंतुलित प्रवर्तन का एक पैटर्न है, जिसमें अधिकांश राजनेताओं की जांच विपक्ष से की जाती है। आलोचकों का आरोप है कि सरकार ई.डी. को राजनीतिक पैंतरेबाजी के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रही है, जिसमें महत्वपूर्ण राज्यों में दलबदल को प्रेरित करना भी शामिल है। 2014 के बाद से, विशेष रूप से भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के तहत, ऐसी जांचों में उल्लेखनीय वृद्धि, कानून के चयनात्मक अनुप्रयोग और लोकतांत्रिक मानदंडों के क्षरण के बारे में चिंता पैदा करती है।

ई.डी. द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पी.एम.एल.ए.) का उपयोग विशेष रूप से विवादास्पद है, विशेष रूप से 2019 में विवादास्पद संशोधनों के बाद जिसने एजेंसी को व्यापक शक्तियां प्रदान कीं। विपक्षी नेताओं का तर्क है कि इन संशोधनों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने और असहमति को दबाने, लोकतंत्र के सिद्धांतों और कानून के शासन को कमजोर करने के लिए किया गया है।

यह कोई नया चलन नहीं है। यह भी कोई रहस्य नहीं है कि कांग्रेस सहित सत्तारूढ़ दलों ने विपक्षी दलों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए कानूनी तंत्र का इस्तेमाल किया है। अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा एक प्रणालीगत है और एक विशिष्ट नेता से परे, बल्कि एक ही पार्टी और एक ही नेता के भीतर सत्ता की एकाग्रता तक फैला हुआ है। भारतीय आम चुनाव 2024 से पहले की घटनाएं चुनावी अखंडता की रक्षा करने और राजनीतिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए चुनावी अनियमितताओं, निष्पक्षता और निरीक्षण तंत्र के बारे में चिंताओं को संबोधित करना आवश्यक है।

इसी प्रकार, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कानूनी संस्थानों के दुरुपयोग को रोकने और कानून के निष्पक्ष और निष्पक्ष कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाने चाहिएं। केवल इन सिद्धांतों को कायम रख कर ही भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपनी स्थिति बनाए रख सकता है और अपने नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है।

मनमोहन बनाम मोदी

–अरविंद सुब्रमण्यम–

मोदी सरकार के 10 साल पूरे होने पर स्वाभाविक रूप से मनमोहन सिंह सरकार के पिछले 10 वर्षों के साथ तुलना की जाने लगी है। लेकिन आध्यक्ष क्षेत्र में, यह राजनीति के दोनों पक्षों में चयनात्मक तर्क और संयोजक स्मृतिलोप के साथ एक झूठी बहस है। मोदी सरकार के 10 साल पूरे होने पर स्वाभाविक रूप से मनमोहन सिंह सरकार के पिछले 10 वर्षों के साथ तुलना की जाने लगी है। लेकिन आध्यक्ष क्षेत्र में, यह राजनीति के दोनों पक्षों में चयनात्मक तर्क और संयोजक स्मृतिलोप के साथ एक झूठी बहस है। पक्षपातपूर्ण राजनीतिक लड़ाइयां स्वाभाविक हैं। लोकतंत्र में हर पार्टी को खुद को दूसरे से अलग करना होता है। लेकिन राष्ट्र–निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, प्रत्येक सरकार अपनी गलतियों से सीखते हुए अपने पूर्ववर्ती के कार्यों पर निर्माण करती है और भारतीय अर्थव्यवस्था की पिछले 2 दशकों की सफलताओं और कमियों का आकलन करने की भावना भी यही होनी चाहिए।

सबसे पहले और सबसे आगे कमरे में भूत–प्रेत प्रणब मुखर्जी हैं। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यू.पी.ए.) सरकार और विशेष रूप से कांग्रेस ने अपने दूसरे कार्यकाल में वित्त मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल पर एक अदृश्य आवरण डाल दिया है। कोई यू.पी.ए. सरकार की 10 वर्षों की सफलताओं के बारे में जो भी सोचता है, और दिवंगत मुखर्जी के दुर्जय राजनीतिक कौशल और कांग्रेस पार्टी और भारतीय लोकतंत्र दोनों में योगदान के बारे में जो भी सोचता है, यह निर्विवाद है कि मुखर्जी का शासनकाल एक निरंतर आर्थिक आपदा थी, यकीनन भारत के इतिहास में सबसे बुरे दौर में से एक।

भारत में पूर्व प्रभावी कराधान, गैर–जिम्मेदार मैक्रो–आध्यक्ष और राजकोषीय नीति, और अनियंत्रित, सभी के लिए मुक्त भ्रष्टाचार देखा गया, जिसमें 'फोन–बैंकिंग बुरे शासन के समृद्ध शब्दकोष में प्रवेश कर रही थी। विकास में गिरावट आई, मुद्रास्फीति बढ़ गई, बैंकिंग प्रणाली कमजोर हो गई और लगभग– 2013 के संकट के बाद प्रणब को शासन करने में असमर्थता हुई। मुखर्जी यू.पी.ए. सरकार के लिए घातक साबित हुए और आर्थिक नेतृत्व के लिए मममोहन सिंह की प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक साबित हुए। जहां कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी के लिए गुमनाम रहने की कामना की,वहीं मोदी सरकार ने उन्हें सम्मान दिया। इसने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया और उन्हें उनके खराब आध्यक रिकॉर्ड के साथ–साथ एस. राधाकृष्णन, मदर टेरेसा, नैल्सन मंडेला, सी.वी. रमन, अब्दुल कलाम, सी. राजगोपालाचारी के समान ही सम्मान दिया।

क्या यह पुरस्कार किसी साथी, करीबी, वैचारिक यात्री को सम्मानित करने के लिए था या आर्थिक अराजकता पैदा करने के लिए कृतज्ञता के रूप में था, जिसने मोदी सरकार के उदय में योगदान दिया। एक वास्तविक द्विदलीय भावना के कारण, हम ये बातें कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन यह सवाल तो उठता ही है कि क्या मनमोहन सिंह का लगभग आधा आर्थिक शासन ऐसा बुरा ही था? इसके मुख्य वास्तुकार को ईनाम क्यों? दोनों पक्षों की चयनात्मकता भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भारत की उपलब्धियों तक फैली हुई है। मोदी सरकार यू.पी.ए. सरकार और पहली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एन.डी.ए.) सरकार दोनों को बिल्डिंग ब्लॉक बनाने के लिए पर्याप्त रूप से श्रेय दिए बिना इन उपलब्धियों को अपने लिए उपयुक्त बनाने की कोशिश करती है। बुनियादी ढांचे की क्रांति को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) से शुरू किया जा सकता है। बदले में, कांग्रेस मोदी सरकार के तहत भौतिक बुनियादी ढांचे के निर्माण की गति में तेजी को अपर्याप्त रूप से स्वीकार करती है और डिजिटल क्रांति के मामले में, जबकि उसने नंदन नीलकणि के तहत महत्वपूर्ण बीज बोए, लेकिन उनके अंकुरण को रोक दिया और यह मोदी सरकार ही थी जिसने जनधन योजना का पुनर्निर्माण किया। मोदी सरकार को पूर्व सरकार को धन्यवाद देना चाहिए और इसके मूल्य को बढ़ाना चाहिए, जिससे मोदी की सरकार को सुधार में मदद मिली।

कल्याणकारी राज्य के मामले में, यू.पी.ए. सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य सुरक्षा और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) के तहत रोजगार गारंटी पर जोर देकर सामाजिक सुरक्षा जाल के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति की।

न्यायालय में लम्बित वादों का हो समय से निस्तारण–डीएम

संवाददाता–श्रावस्ती। जिलाधिकारी कृतिका शर्मा ने शनिवार को तहसील भिनगा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अभिलेखागार में जाकर राजस्व रिकार्डों के बस्तों का अवलोकन किया। साथ ही सभी रिकार्डो के व्यवस्थित रख रखाव व साफ–सफाई का निर्देश दिया। जिलाधिकारी कृतिका शर्मा ने एसडीएम न्यायालय, तहसीलदार न्यायालय, लेखपाल अनुभाग, रजिस्टार, कानूनगो अनुभाग, रिकार्ड रूम, संग्रह अनुभाग का निरीक्षण किया। डीएम ने नजारत अनुभाग पहुंच कर आरसी पंजिका, स्थायी अग्रिम पंजिका, कैदियों व गवाहों के खुराक धन की प्राप्ति और शुल्क पंजिका, व्यक्तिगत धनराशि के रूप में लिया गया शुल्क व बिक्री अभिदान पंजिका, राजकीय कोष पंजिका, न्यायालय सम्पत्ति बिक्री पंजिका, आय व व्यय पंजिका, शिकायत पंजिका, डाक टिकटों का लेखा एवं तामीला पंजिका आदि की जांच की। साथ ही बड़े बकायदारों की सूची बनाकर आरसी वसूली करने को निर्देशित किया। डीएम ने एसडीएम को न्यायालय पर लम्बित वादों का समय से निस्तारित करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि तहसील में आने वाले हर फरियादियों की समस्याओं को सूचीबद्ध किया जाए और उनका निराकरण भी समय सीमा के अन्दर किया जाए। डीएम ने कहा कि तहसील में खतौनी प्राप्ति के लिए आने वाले किसानों को निर्धारित शुल्क में ही खतौनी उपलब्ध कराया जाय। निर्धारण से अधिक शुल्क लेने पर कार्रवाई होगी। इस दौरान एसडीएम पीयूष जायसवाल, एसडीएम पीके राय, तहसीलदार भिनगा जागृति सिंह, नायब तहसीलदार राघवेन्द्र पाण्डेय आदि मौजूद रहे।

बालगृह से पढ़ने गया कक्षा 5 का छात्र अचानक हुआ गायब, मचा हड़कंप

संवाददाता–गोण्डा। ग्रामीण विकास समिति के माध्यम से संचालित बालगृह से 4 बच्चों को प्रतिदिन कंपोजिट विद्यालय पंतनगर संस्था के वाहन और वहां के कर्मचारियों की देखरेख में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाता है। शुक्रवार को प्रतिदिन की भांति चार बच्चे विद्यालय गए थे। जिसमें से मध्यान भोजन खाते समय उत्तम कुमार कक्षा 5 का छात्र 12 वर्ष अचानक विद्यालय परिसर से लापता हो गया। साथ में गए कर्मचारियों ने काफी खोजबीन किया। लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कर्मचारियों ने इसकी सूचना चीफ कोऑर्डिनेटर को दी। उसके बाद अधिकारियों को कोऑर्डिनेटर के माध्यम से अवगत कराया गया। जिले में ग्रामीण विकास समिति के माध्यम से संचालित बालगृह के सभी बच्चों का पंतनगर स्थित कंपोजिट विद्यालय में प्रतिदिन संस्था के वाहन और कर्मचारियों की देखरेख में पढ़ने जाते हैं। शुक्रवार को बालगृह से चार छात्र पढ़ने गए थे। जिसमें उत्तम कुमार 12 वर्ष अचानक विद्यालय से लापता हो गया। बच्चों के गायब होने के बाद संस्था में हड़कंप मच गया। संस्था के चीफ कोऑर्डिनेटर उपेंद्र सिंह ने इसकी सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी को दिया। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बाल गृह पहुंचकर मौके का निरीक्षण किया। उसके बाद नगर कोतवाली में तहरीर देकर बच्चे के गायब होने की सूचना दर्ज कराई गई है। बच्चों की देखरेख के लिए उनके साथ गए संस्था के दो कर्मचारी दिनेश कुमार, प्रसून सिंह, सोहनलाल एवं सुरेन्द्र की निगरानी में बच्चे प्रतिदिन विद्यालय में पढ़ने जाते थे। वहां पर मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि दोपहर बाद 2:30 बजे बालक उत्तम कुमार 12 वर्ष कक्षा–5 का छात्र है। वह विद्यालय परिसर में उपस्थित नहीं मिला। जिससे कर्मचारियों को ज्ञात हुआ कि बच्चा गायब हो गया। कर्मचारियों ने इसकी सूचना संस्था प्रभारी को दी। उसके बाद प्रभारी ने उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया। उसके बाद जिला प्रोबेशन अधिकारी ने नगर कोतवाली में छात्र के गायब होने की गुमशुदगी दर्ज कराई गई है। इससंबंध में जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष कुमार सोनी ने बताया कि पूरे मामले की लिखित सूचना नगर कोतवाली पुलिस को दी गई है। वह अग्रिम विधिक कार्यवाई कर रही है। संस्था के लोग भी बच्चों की तलाश कर रहे हैं।

बहराइच रोड पर दो घंटे तक लगा रहा जाम, राहगीर हुए परेशान

संवाददाता–बलरामपुर। बलरामपुर–बहराइच मार्ग स्थित पहलवारा मोहल्ला में शनिवार को मुख्य मार्ग पर ट्रक खराब होने से दो घंटे तक जाम लगा रहा। जाम हटाने में यातायात कर्मियों को करीब तीन घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जाम में फंसे लगभग लगभग डेढ़ हजार राहगीरों को दिक्कतें उठानी पड़ीं। मुख्य बाजार के रास्ते बड़े वाहनों का आवागमन होने से जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। फुलवरिया बाईपास का निर्माण तो हो गया, लेकिन ओवरलोड वाहन उस पर चढ़कर नहीं निकल पाते हैं।

शनिवार सुबह 11 बजे पहलवारा मोहल्ला के निकट बहराइच की ओर जा रहा ट्रक अचानक खराब हो गया। कुछ बड़े वाहन जल्दी निकलने के प्रयास में आमने–सामने आ गए। 15 मिनट बाद स्थिति यह हो गई कि बाइक निकलने भर की भी जगह नहीं बची। इसी बीच ट्रेन आने से झारखंडी रेलवे क्रासिंग भी बंद हो गया। धीरे–धीरे जाम बढ़ता गया।

बहराइच रोड पर पीपल तिराहा से आगे तक वाहनों की लम्बी कतार लग गई। इधर रेलवे क्रासिंग से एमपीपी इंटर कॉलेज तक वाहनों की लाइन लग गई। फाटक खुलने के बावजूद जाम नहीं हटा। बाइक चालक भी जाम में फंसे रहे। वे बाइक मोड़कर दूसरे रास्ते से नहीं निकल सकते थे। सड़क के बीचोबीच खराब ट्रक को बाहर निकालने की कवायद कामयाब नहीं हो सकी। बस स्टेशन मोड़ पर सीवर लाइन बिछाने के लिए गहरा गड्ढा खोदा गया है। वाहनों को बस स्टेशन मोड़ की ओर भी नहीं घुमाया जा सकता था। वाहनों का काफिला जाम में फंसा रहा। पीपल तिराहा पुलिस चौकी से घूमकर तुलसीपुर मार्ग पर जाना भी संभव नहीं था। खराब ट्रक को हटवाने के लिए यातायात कर्मी सक्रिय हुए। ट्रक को किनारे करने में दो घंटे का समय लगा। उसके बाद रास्ता खुला। अवकाश का दिन होने के बावजूद भीड़ देखकर लोग हैरान रह गए। पूरी तरह आवागमन बहाल होने में तीन घंटा समय बीत गया।

अरविंद सिंह, जिलाधिकारी ने कहा कि झारखंडी रेलवे क्रासिंग पर उपरगामी सेतु बनाने की योजना बनकर तैयार है। रेलवे, लोक निर्माण व नेशनल हाईवे विभाग ने सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। शासन से स्वीकृति मिलते ही ओवरब्रिज का निर्माण शुरू करा दिया जाएगा, जिससे जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। रिंग रोड निर्माण शीघ्र ही शुरू होने वाला है, इससे भी जाम की समस्या पर विराम लगेगा।

नकल पर अंकुश लगाने को उत्तर पुस्तिकाओं का बदला रंग

संवाददाता–बलरामपुर। यूपी बोर्ड परीक्षा जैसे–जैसे नजदीक आ रही है वैसे–वैसे परीक्षार्थियों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। तैयारी करने वाले छात्र नकल पर अंकुश लगाने की कवायद को हितकर मान रहे हैं। वहीं पर नकलचियों पर अंकुश लगाने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस बार सख्त इंतजाम किए हैं। इस बार हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए परीक्षा के दौरान उत्तर पुस्तिकाओं का रंग अलग तरीके का किया गया है, ताकि परीक्षा के दौरान कॉपियां बदल कर अथवा कॉपी के बीच के पेज निकालकर होने वाली नकल को रोका जा सके।

जिले में यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए 64 केंद्र बनाए गए हैं। इन केन्द्रों पर करीब 35 हजार परीक्षार्थी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा देंगे। बोर्ड परीक्षा शुरू होने के पहले ही मुख्यालय को उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध कराकर परीक्षा केंद्रों को आवंटित किए जा रहे हैं। इस बार परीक्षा में हाई स्कूल की एक कॉपी का रंग डार्क ब्राउन एवं बी कॉपी का रंग डार्क वॉयलेट होगा। इसके अलावा हाई स्कूल एवं इंटर की उत्तर पुस्तिकाओं का रंग भी अलग–अलग रखा गया है। उत्तर पुस्तिका एवं कवर पृष्ठ के साथ अंतिम पृष्ठ पर माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अपना लोगों लगाया है। इस बार जो उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षा के लिए मंगाई गई है उसकी सिलाई अलग से कराई गई है, ताकि बीच के पेज को निकालना संभव न हो सके। यह व्यवस्था शासन ने नकल पर अंकुश लगाने को लेकर किया है। गोविंद राम डीआईओएस ने कहा कि यूपी बोर्ड परीक्षा की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले में 64 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक केंद्र पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है। जहां पर उत्तर पुस्तिका एवं प्रश्न पत्र कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखे जाएंगे। नकल विहीन शांतिपूर्ण परीक्षा कराना प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है।

डाकघर में न्यूनतम राशि जमा नहीं किया तो भरेंगे पेनाल्टी

संवाददाता–महराजगंज। डाकघर के पीपीएफ व सुकन्या समृद्धि योजना के निवेशकों को न्यूनतम राशि जमा करना होगा। किसी वजह से यदि निवेशक पिछले वित्तीय वर्ष की न्यूनतम राशि जमा नहीं कर पाए हैं, तो उन्हें पेनाल्टी देना पड़ेगा। डाक विभाग में पीपीएफ व सुकन्या समृद्धि योजना में निवेशकों की संख्या बढ़कर करीब पांच लाख तक पहुंच गई है। पर अभी भी तमाम निवेशक समय से निवेशक नहीं कर रहे हैं। कई हजार निवेशकों ने सुकन्या योजना में न्यूनतम राशि भी जमा नहीं किया है। ऐसे निवेशकों को पेनाल्टी शुल्क 50 रुपये देना पड़ेगा। डाकघर के नियम के मुताबिक पीपीएफ योजना के तहत किसी भी निवेशक को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम पांच सौ रुपये जमा करना अनिवार्य है। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना में भी न्यूनतम 250 रुपये सालाना जमा करना जरूरी है। सोनेलाल पटेल, निरीक्षक डाक ने कहा कि जिन निवेशकों ने पीपीएफ व सुकन्या योजना में न्यूनतम राशि जमा नहीं किया है। ऐसे निवेशकों को पैसा जमा करने के दौरान पेनाल्टी देना पड़ेगा। निवेशक पेनाल्टी शुल्क जमा करके खाते को सक्रिय करा सकते हैं।

देशी तमंचे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

संवाददाता–श्रावस्ती। अपराध नियंत्रण को लेकर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने देशी तमंचा व कारतूस बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एसपी के निर्देशन में शनिवार को क्षेत्र देखभाल के लिए सिरसिया थाने के प्रभारी निरीक्षक भानु प्रताप सिंह पुलिस टीम के साथ भ्रमण कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने भदिला गांव स्थित नहर पुलिया के पास से एक व्यक्ति के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा व दो कारतूस बरामद किया।

बरामद मंचा व कारतूस को जब्त कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार लिया। आरापी की पहचान राम कुमार पुत्र राम खेलावन निवासी भदिला थाना सिरसिया के रूप में हुई। आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी टीम में प्रभारी निरीक्षक के साथ उपनिरीक्षक अनिरुद्ध कुमार सिंह, मुख्य आरक्षी जय प्रकाश यादव व आरक्षी रिषभ गौड़ शामिल रहे।

सभी स्कूलों में बनेगी आपदा प्रबंधन समिति, शिक्षकों को मिला प्रशिक्षण

संवाददाता–श्रावस्ती। सभी स्कूलों में आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। इसके लिए सभी स्कूलों के एक एक शिक्षक को रेडक्रॉस व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के संयोजक अरुण कुमार मिश्र ने बताया कि प्रत्येक विद्यालय से एक शिक्षक को प्रशिक्षित किया गया है।

बेसिक शिक्षा के 825 अध्यापकों का प्रशिक्षण पूरा हो गया है। सभी शिक्षकों को ब्लाकवार प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया था। लेकिन यह ध्यान रखा गया था कि एकल विद्यालय बंद न हों। एकल विद्यालय के शिक्षकों को किसी रविवार को बुलाकर शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जायेगा। इसके अलावा माध्यमिक व डिग्री कालेजों के शिक्षकों व प्रत्येक ग्राम सभा से चार सदस्यों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इन सभी को मिलाकर प्रत्येक ग्राम सभा में आपदा टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा। इसका प्रयोग प्रत्येक आपदा से पूर्व तैयारी, बचाव व पुनर्वास का प्रशिक्षण दिया जायेगा। सभी प्रशिक्षणार्थियों के मोबाइल नंबर इकट्ठे किए जा रहे हैं इनका मोबाइल ग्रुप बनाकर पूरे जनपद में सघन पूर्व सूचना तंत्र विकसित किया जाएगा। ताकि किसी भी आपदा की पूर्व सूचना को तत्काल ग्राम स्तर तक भेजा जा सके । सभी प्रशिक्षणार्थियों को भारत सरकार व राज्य सरकार की ओर से घोषित आपदाओं, उनके प्रभाव व उनके बचाव के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी को सीपीआर व हार्टअटैक से बचाव का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यातायात विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा व अग्निशमन विभाग की ओर से अग्निकांड से सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण सामग्री को इस प्रकार बनाया गया है कि वह प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों के दैनिक जीवन में भी लाभकारी सिद्ध हो।

थाना दिवस में 55 में से महज तीन शिकायतों का निस्तारण

संवाददाता–श्रावस्ती। सभी थानों में शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारियों की ओर से लोगों की शिकायत सुनी गई। थाना समाधान दिवस में कुल 55 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से महज तीन शिकायतों का ही निस्तारण हो सका। कोतवाली भिनगा व थाना सिरसिया में आयोजित थाना समाधान दिवस में जिलाधिकारी कृतिका शर्मा व पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने जनसुनवाई की। कोतवाली भिनगा में नौ व थाना सिरसिया में 11 शिकायती पत्र प्राप्त हुए। जिसमें थाना सिरसिया में दो शिकायतों का निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया। इसी तरह से पुलिस उपाधीक्षक इकौना संतोष कुमार ने थाना नवीन मॉडर्न श्रावस्ती में फरियादियो की शिकायत सुनी। यहां दो शिकायती पत्र प्राप्त हुए। निस्तारण किसी का नहीं हो सका। पुलिस उपाधीक्षक जमुनहा सतीश कुमार शर्मा ने थाना मल्हीपुर में लोगों की शिकायत सुनी और प्राप्त सात प्रार्थना पत्रों में से एक का निस्तारण किया। इसके अलावा थाना गिलौला में तीन, थाना इकौना में 13, थाना सोनवा में तीन, थाना हरवत्तनगर गिरंट में सात शिकायती पत्र प्राप्त हुए।

अब टेढ़ी नदी का होगा उद्धार, मनरेगा श्रमिक करेंगे भगीरथ प्रयास

संवाददाता–बहराइच। राजस्व अभिलेखों में सिमटी व तीन दशक से अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रही टेढ़ी नदी के उद्धार को मनरेगा श्रमिक अब भगीरथ बनेंगे। तीन ब्लॉकों के सिंचाई समेत जलसंचयन का आधार रही नदी के जीर्णोद्धार के लिए योगी सरकार ने खजाना खोला है। दो करोड़ खर्चकर नदी की सिल्ट सफाई होगी। नए घाट भी बनाए जाएंगे, ताकि नदी की अविरल धारा प्रवाहित हो सके। बसंत पर्व के दिन टेढ़ी के उद्धार का श्रीगणेश होगा। जिले के चितौरा से निकलकर टेढ़ी नदी , हुजूरपुर, पयागपुर व विशेश्वरगंज ब्लॉक से होते हुए गोंडा जनपद में प्रवेश कर जाती है। तीन ब्लॉकों के लिए के 61 किलोमीटर के दायरे में सिंचाई व जल संचयन को लेकर महत्वपूर्ण रही नदी उपेक्षा का शिकार रही। जगह–जगह लोगों के अतिक्रमण की वजह से सिमट गई है। हालात ये हो गए हैं कि अविरल धारा गायब है। पानी भी नदी में नहीं रुकता है। नदी की सफाई कार्य को लेकर पूर्व में कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने आवाज भी उठाई है। नदी के जीर्णोद्धार को लेकर कई बार शासन को प्रस्ताव भेजा गया। अब योगी सरकार ने नदी को पुराने रंगत में लाने के लिए दो करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। जिससे नदी की सिल्ट सफाई संग हर नदी के किनारे बसे गांवों के पास घाट बनाने का भी खाका खींचा गया है, ताकि ग्रामीण नदी में आस्था की डुबकी भी लगा सकें। नदी से लगने वाले हर ग्राम पंचायत के 100 से लेकर 150 मनरेगा श्रमिक कार्य में लगाए जाएंगे। इससे जहां नदी का कायाकल्प होगा वहीं श्रमिकों को गांव में ही रोजगार भी मिल सकेगा। 14 फरवरी को सबंत पर्व के शुभ लग्न में नदी के जीर्णोद्धार के लिए अभियान का आगाज होगा। केडी गोस्वामी, उपायुक्त, मनरेगा ने कहा कि टेढ़ी नदी के साफ होने से पानी का संरक्षण होगा। जलधारा की क्षमता बढ़ेगी। दो करोड़ का बजट खर्च होगा। बसंतोत्सव पर जीर्णोद्धार का श्रीगणेश होगा।

शहर के 27 केंद्रों पर एआरओ व आरओ की परीक्षा आज

संवाददाता–गोंडा। जिले में यूपीएससी की आयोजित आरओ व एआरओ की परीक्षा 27 केंद्रों पर रविवार को आयोजित की जाएगी। दो पालियों में परीक्षा कराई जाएगी। सुबह की पाली में 9रू30 से 11रू30 तक और दूसरी पाली में 2रू30 बजे से 3रू30 तक परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा में 11616 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी है।

परीक्षा के लिए स्टैटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। परीक्षा शुरू होने के डेढ़ घंटे पहले स्टैटिक मजिस्ट्रेट परीक्षा केंद्रों पर पहुंचेंगे। शहर की सड़कों पर लोग आसानी से परीक्षा केंद्रों पर पहुंच सके इसके लिए यातायात व्यवस्था बेहतर रखने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम नेहा शर्मा ने एडीएम चंद्रशेखर और डीआईओएस राकेश कुमार को परीक्षा का नोडल अधिकारी बनाया है। सीआरओ महेश प्रकाश कंट्रोल रूम से पैनी नजर रखेंगे। डीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों को शांतिपूर्ण परीक्षा में सहयोग करने के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा है। डीआईओएस परीक्षा केंद्रों की सभी खामियों को दूर करेंगे। इन परीक्षा केंद्रों पर शामिल होंगे अभ्यर्थीरू जिले में रविवार को लोक सेवा आयोग की आयोजित समीक्षा अधिकारी की परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 27 केंद्रों पर कुल 11616 अभ्यार्थी परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे।

इनमे फखरूद्दीन अली अहमद इंटर कॉलेज में 384 , एलबीएस पीजी कॉलेज विज्ञान परिसर में 480 , शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज में 480, सरस्वती विद्या मंदिर में 480, सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंड्री स्कूल में , भइया राघव राम इंटर कॉलेज में , जीजीआईसी में 480, एसटीवीएम इंटर कॉलेज में 384, स्वामी विवेकानन्द इंटर कॉलेज में 480,रवि चिल्ड्रन एकेडमी में 384, महर्षि विद्या मंदिर में 384 , सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्थली इंटर कॉलेज में 480, एम्स इंटर कॉलेज में 480 , नारायना पब्लिक स्कूल में 480, जिगर मेमोरियल इंटर कालेज में 480 , सेंट एमआर जयपुरिया स्कूल में 384 , सर सैय्यद गर्ल्स इंटर कॉलेज में 384, फातिमा स्कूल में 480 , गांधी विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 480 , सरस्वती विद्या मंदिर बड़गांव में 384, राजकीय आश्रम पद्यति विद्यालय में 384 , सेंट जेवियर्स स्कूल पंत नगर में 480 , रघुकुल महिला विद्यापीठ में , एससीपीएम मेडिकल कॉलेज हारीपुर में कुल 1152 अभ्यार्थी शामिल होंगे। इनमें कुल 11 हजार से अधिक अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे।

27 स्टैटिक और 9 सेक्टर मजिस्ट्रेट संभालेंगे जिम्मेदारी रू समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी की दो पालियों में आयोजित की जाने वाली परीक्षा को लेकर आयोग के निर्देश पर डीएम नेहा शर्मा ने सूचितापूर्ण परीक्षा संपन्न कराने के लेकर 27 स्टैटिक और 9 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए हैं। वहीं 7 स्टैटिक और 4 सेक्टर मजिस्ट्रेट को रिजर्व में रखा गया है। जिसमे जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी शामिल हैं।

शादी के दिन दबिश देना कोतवाल को पड़ गया महंगा, जांच में मिले दोषी एसपी ने किया निलंबित

संवाददाता–गोण्डा। पुलिस अधीक्षक ने एक पीड़ित की शिकायत पर मामले की जांच कराई। जांच में प्रभारी निरीक्षक के एकतरफा कार्यवाई होने की पुष्टि तथा समाज में पुलिस की छवि को धूमिल करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। गोंडा जिले के मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के मनकापुर गांव के रहने वाले मोहम्मद शाद और मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के शेखपुरवा गांव में रहने वाले मालू में रूपयों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। जिसमे जमीन का बैनामा करने के लिए मोहम्मद शाद ने पैसे लिए थे। रकम की वापसी के लिए दूसरे पक्ष से नोकझोंक हो रहा था। लेकिन उसे अपना रुपया वापस नहीं मिल रहा था। जिसमें रुपया वापस करने वाले पक्ष के यहां आज शनिवार को शादी है। जिससे घर में शादी की रस्में चल रही थी। इसी शादी का हवाला देकर पैसा वापस करने से मना करते हुए शादी के बाद रुपए वापस देने की बात कर रहा था। जबकि रुपया मांगने वाला पक्ष तत्काल पैसे की मांग कर रहा था। इस बाबत दोनों में सामंजस्य नहीं बना और मामला मनकापुर पुलिस में पहुंच गया। 8 फरवरी को मनकापुर पुलिस में शिकायत किया कि विपक्षी ने जमीन के सौदे को लेकर रुपया ले लिया है। मामले में मनकापुर कोतवाल राजकुमार सरोज ने एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए उसके घर में बिना मुकदमा दर्ज किए दबिश दी। पैसों के लेन देन के प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए 151 सीआरपीसी के तहत चालान कर दिया। मामले में पीड़ित ने 9 फरवरी को पुलिस अधीक्षक गोंडा से न्याय की गुहार लगाई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने प्रभारी निरीक्षक पर लगाए गए आरोपी की जांच पुलिस क्षेत्राधिकारी मनकापुर से कराई। पुलिस क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार सिंह के जांच में प्रभारी निरीक्षक मनकापुर राजकुमार सरोज प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने मनकापुर कोतवाल राजकुमार सरोज के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

महिलाओं के साथ भाजपा ने की चाय पर चर्चा

संवाददाता–श्रावस्ती। भारतीय जनता पार्टी के नारी शक्ति अभियान के तहत शनिवार को स्वयं सहायता समूह तथा एनजीओ की महिलाओं के साथ चाय पर चर्चा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष उदय प्रकाश त्रिपाठी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में लोकसभा संयोजक शंकर दयाल पाण्डेय उपस्थित रहे। जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर में एनजीओ तथा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के साथ चाय पर चर्चा का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष उदय प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नारी की गरिमा व सुरक्षा और उनके सम्मान व स्वावलंबन के लिए बेहतर वातावरण बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के कोने कोने में कार्य कर रही महिलाओं को केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। जिसको साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। विशिष्ट अतिथि शंकर दयाल पाण्डेय ने कहा कि भाजपा का उद्देश्य है कि पूरे देश में इस अभियान के तहत एक करोड़ स्वयं सहायता समूह एवं एनजीओ तक संपर्क करके 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प से जोड़ना है। चाय पर चर्चा कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम के संयोजक जिला महामंत्री दिवाकर शुक्ला ने किया। इस दौरान एनजीओ और सहायता समूह चला रही विभिन्न महिलाओं ने अपने कार्य करने के तरीके, कैसे ससफल उद्यमी बने, कैसे अपनी आय बढ़ाये इसके सम्बंध में अपने अनुभवों को उपस्थित महिलाओं से सांझा किया। इस दौरान अपने क्षेत्र में अपने कार्यों के माध्यम से अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाली महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। चाय पर चर्चा कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष पूजा पाण्डेय, भाजपा नेत्री माधुरी सिंह त्रिपाठी, ब्लॉक प्रमुख सिरसिया अमित सिंह, जिला मीडिया प्रभारी संजू तिवारी, अनिल मिश्रा, नेकराम पाण्डेय तथा भारी संख्या समूह व एनजीओ की महिलाएं मौजूद रहीं।

जन जातीय संस्था बनाएगी 20 हजार सदस्य, खेम सिंह राना बने अध्यक्ष

संवाददाता–बलरामपुर। महाराणा प्रताप जन जातीय सेवा संस्थान की बैठक बालापुर मां बालेश्वरी मंदिर पर की गई। बैठक की अध्यक्षता चेत राम थारू ने किया। जिसमें सर्व सम्मति से खेम सिंह राना को गैंसडी ब्लाक का अध्यक्ष चुना गया। संस्था के अध्यक्ष मदनलाल जायसवाल ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि संस्था गरीबो के अधिकारों को लेकर लडाई लड़ रही है। थारू जनजाति क्षेत्र में जन जागरूकता अभियान चलाकर सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रही है, ताकि समाज के अंतिम छोर पर बैठे गरीबों को योजनाओं का लाभ मिल सके। मदन लाल जायसवाल ने बताया कि गैंसडी विधानसभा में महाराणा प्रताप जन जातीय सेवा संस्थान के 20 हजार सदस्य बनाए जायेंगे। ब्लाक गैंसडी कार्यकारणी में संयोजक प्रभू नाथ थारू, उपाध्यक्ष बजरंग बहादुर, राम करन थारू, दीनानाथ प्रधान, महामंत्री राम धीरज थारू, मंत्री रूद्र नरायन, आदर्श थारू, मीडिया प्रभारी बिनोद श्रीवारत्तव, संगठन मंत्री सत्य नरायन थारू, व्यवस्थापक शनि जायसवाल, आडिटर राजेश थारू सहित भारी संख्या में थारू जनजाति के लोग मौजूद रहे।

श्री राम जानकी खलवा मंदिर के महंत बने राम बिहारी दास

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

अयोध्या। अयोध्या के रायगंज स्थित श्री राम जानकी खलवा मंदिर स्वर्णखनी कुंड अयोध्या के महंत बने राम बिहारी दास, महंत रामध्वज दास चेला स्वर्गीय रामबालक दास का स्वर्गवास हो गया था मंदिर की व्यवस्था ठाकुर जी का भोग राज सुचारू रूप से चला रहे इसके लिए अयोध्या के संतों महंतों ने स्वर्गीय रामध्वज दास के शिष्य राम बिहारी दास को वैष्णो सनातन परंपरा के अनुसार कंढ़ी चद्दर तिलक देकर के श्री राम जानकी खलवा मंदिर का महंत बनाया। महंत राम बिहारी दास ने बताया कि गुरुदेव भगवान संत थे और आश्रम में प्रतिदिन सैकड़ो संतो श्रद्धालुओं का भंडारा चलता था ठाकुर जी की सेवा के साथ गौ सेवा सेत सेवा निरंतर होती थी उत्सव सवैया मनाए जाते थे वह सनातन परंपरा के अनुसार निरंतर चलता रहेगा उसमें कोई कमी नही आएगी। इस अवसर पर जानकी घाट बड़ा स्थान के महंत जन्मेजय शरण, बड़ा भक्तमाल के महंत स्वामी अवधेश कुमार दास डांडिया मंदिर के महंत गिरीश दास बड़ी छावनी के पुजारी विष्णु दास महंत रामकुमार दास महंत रामस्वरूप दास महंत सूरज दास महंत राम मोहनदास महंत अजय दास गौरव दास सहित सैकड़ो संतों महंतों कंठी चद्दर देकर महंती दी।

छह वर्ष बीत गए लाभार्थियों को नहीं मिले आयुष्मान कार्ड

संवाददाता–बलरामपुर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उतरौला में कम्प्यूटर पर फीड किए गए शहरी आयुष्मान के करीब सात हजार लाभार्थियों को योजना शुरू होने के छह वर्ष बीतने के बाद भी आयुष्मान कार्ड नहीं मिल सके हैं। आयुष्मान कार्ड धारकों को कार्ड न मिलने से लाभार्थी इलाज की सुविधा नहीं ले पा रह हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उतरौला में आयुष्मान योजना 2018 से शुरू हुई थी। इस योजना में शहरी क्षेत्र नगर पालिका परिषद उतरौला वासियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए अब तक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में करीब 2500 लाभार्थियों तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में 236 फैमिली एवं 372 अन्त्योदय का आवेदन कम्प्यूटर में फीड किया गया है। इसी तरह अर्बन एरिया के करीब दो हजार लाभार्थियों का आवेदन कम्प्यूटर में फीड कर दिया गया। लाभार्थियों का आवेदन फीड होने के बाद उनको अस्थाई आयुष्मान पत्र दे दिया गया, लेकिन आयुष्मान कार्ड आज तक नहीं दिया गया। आयुष्मान कार्ड न होने से उसे अस्पतालों में एक्टिवेट नहीं हो सका। आयुष्मान कार्ड का एक्टिवेट न होने से अस्पतालों में उन्हें आयुष्मान कार्ड से इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है। जिस कारण इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ आयुष्मान कार्ड लाभार्थियों को न मिलने से शहरी क्षेत्र के लाभार्थी परेशान हैं। सीएमओ डा. मुकेश कुमार रस्तोगी ने बताया कि प्रकरण की जानकारी हुई है। लाभार्थियों को शीघ्र ही कार्ड दिलाए जाएंगे।

काठमांडू जाने के लिए जनरथ रोडवेज सेवा बंद, दिक्कत में यात्री

संवाददाता–महराजगंज। महराजगंज के रोडवेज यात्रियों को काठमांडू जाने को लेकर काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। रोडवेज विभाग के जिम्मेदारों ने ए

विजय माल्या-नीरव मोदी निकला रुद्रांश, बैंकों में पैठ बनाई फिर ठगा

संवाददाता–गोरखपुर। फर्जी दस्तावेज पर आईसीआईसीआई सहित कई बैंकों से करोड़ों का ऋण लेकर चूना लगाने वाले रुद्रांश पांडेय ने विजय माल्या और नीरव मोदी की तरह पहले बैंकों में पैठ बनाई फिर मोटा चूना लगा दिया। पुलिस की जांच में अब परत दर परत रुद्रांश के कारनामे सामने आ रहे हैं। बैंक में उसकी पैठ इस कदर थी कि दो प्राइवेट बैंकों से दो करोड़ से अधिक का ऋण लेने और उसे नहीं चुकाने के बावजूद उसने दूसरे बैंकों में जालसाजी की पटकथा तैयार कर ली। पुलिस ने उसका पूरा काला चिट्ठा बैंक के सामने रख दिया है, लेकिन अब अपनों की गर्दन फंसती देख बैंक प्रबंधन ने ही कदम पीछे खींच लिए हैं।

बांसगांव का रहने वाला रुद्रांश पांडेय एक–एक कर तीन प्राइवेट बैंकों से ऋण लिया है। आईसीआईसीआई बैंक से उसने 4.45 करोड़ रुपये का ऋण लिया। रकम एक करोड़ से ज्यादा होने की वजह से बैंक कर्मियों ने अपनी नौकरी बचाने के लिए पुलिस में केस दर्ज करा दिया। पुलिस ने जांच शुरू की तो सिस्टम का खेल सामने आ गया। पुलिस की जांच में यह भी सामने आ चुका है कि उसने आईसीआईसीआई के अलावा एक बैंक से 80 लाख और दूसरे प्राइवेट बैंक से 1.20 करोड़ रुपये का ऋण लिया। जिस बैंक से उसने 80 लाख रुपये लिए और न चुकाने पर उसे काली सूची में डाला गया, वहीं पर रुद्रांश ने नया खाता भी खुलवा लिया। बैंक प्रबंधन ने इसे नजरअंदाज कर दिया।

अभी तक दोनों बैंकों की ओर से पुलिस में केस दर्ज नहीं कराया गया है। जांच में जुटी पुलिस चाहती है कि आईसीआईसीआई बैंक ने जो केस दर्ज कराया है, उसी में बैंक कर्मियों सहित पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर दिया जाए। इससे एक संदेश भी जाएगा कि किसी ने इस फर्जी तरीकों से ऋण दिया तो बच नहीं पाएगा। मगर, यह जांच भी अभी भी बैंक तक जाकर रुकी है। बैंक की ओर से अपने दोषी कर्मचारियों का नाम ही नहीं बताया जा रहा है। अब तक पुलिस जांच में जो सामने आया है, उसके मुताबिक, रुद्रांश की एक सीए से गहरी दोस्ती है। उसके पैड का इस्तेमाल किया है। जानकार बाताते हैं, किसी भी फर्म को अगर सीए सत्यापित करके दे देता है तो बैंक फिर उसकी बहुत जांच नहीं करता है। रुद्रांश ने भी ऐसे ही फर्जी दस्तावेज पर ऋण लिया है। उसने सीए से अपने कागजात को सत्यापित कराया और फिर बैंक के चुनिंदा परिचित लोगों से पैरवी कराकर लोग हासिल किया है। आशंका तो यह भी है कि इस काम को करने के लिए बैंक कर्मचारियों का भी अपना हिस्सा है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि पुलिस की जांच में बैंक कर्मचारियों और सीए की भूमिका संदिग्ध आ चुकी है। पुलिस ने बैंक से पत्राचार भी किया है, लेकिन अभी तक बैंक की ओर से सटीक जवाब नहीं आया है कि किस कर्मचारी ने बिना जांच पड़ताल के करोड़ों का ऋण दे दिया है। पुलिस बैंक अधिकारियों के संपर्क में है। जल्द ही आरबीआई और आईसीआई बैंक के हेड क्वाटर को भी पत्र भेजा जाएगा। इस पूरे गिरोह में जो भी शामिल है, सब पर पुलिस साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करेगी। लीड बैंक के मैनेजर मनोज कुमार ने बताया कि ऋण देने को लेकर पहले से ही सख्त गाइड लाइन है। हाउसिंग लोन में तहसील से दस्तावेजों की जांच, वैरीफाई कराया जाता है। जालसाजी के मामले सामने आने के बाद गाइड लाइन की निगरानी सख्ती से करने का निर्देश दिया गया है। सर्किल स्तर पर सभी को प्रबंधकों की इसकी जानकारी दी गई है। मुंबई हेड आफिस से कोई नई गाइड लाइन जारी नहीं हुई है।

अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता रहेगा, व्यापारियों को तीन दिन पहले मिलेगी सूचना

संवाददाता–गोरखपुर। महानगर को स्वच्छ एवं अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नगर निगम का अभियान आगे भी जारी रहेगा। हालांकि जिस दिन अतिक्रमण हटाना होगा, उसके तीन दिन पहले इलाके के व्यापारिक संगठनों को सूचना दी जाएगी। यह आश्वासन महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगवार ने व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों को दी।

नगर आयुक्त सभागार में हुई बैठक में व्यापारिक संगठनों ने विभिन्न ट्रेड के लिए निर्धारित लाइसेंस शुल्क न वसूले जाने की मांग रखी, जिस पर निगम अधिकारियों ने बताया कि कोई नया शुल्क नहीं लिया जा रहा है। नगर निगम को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न शुल्कों की वसूली पर जोर है। व्यापारियों ने बाजार में साफ–सफाई न किए जाने का मसला उठाया। उनकी मांग पर नगर आयुक्त ने आश्वस्त किया कि सफाई और फागिंग के लिए रोस्टर जारी कर सार्वजनिक किया जाएगा। व्यापारियों ने अम्बेडकर चौक पर पटरी व्यापारियों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने की मांग भी की। यह भी मांग किया कि जुर्माने की धनराशि कम की जाए। इसके अलावा सम्पत्तिकर के बकाए में दुकान, गोदाम और अन्य कामर्शियल प्रतिष्ठान सील न करने की मांग की। उनका तर्क था कि व्यवसायियों ने किराए पर दुकान खोली हैं, ऐसे में मकान मालिक के बकाया सम्पत्तिकर के लिए उनका काम काज प्रभावित करना उचित नहीं है। निगम अधिकारियों ने कहा कि वह व्यवहारिक दिक्कतें समझते हैं लेकिन सम्पत्तिकर की वसूली के लिए निगम के पास भी यह अंतिम विकल्प है। इस दौरान नगर आयुक्त ने व्यापारियों से सड़कों से अतिक्रमण हटाने और गलियारे खाली करने की अपील की। कहा कि डोर टू डोर कूड़ा निस्तारण, स्वच्छ भारत अभियान और यूजर चार्ज जमा कराने में सहयोग करें। बैठक में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा, निरंकार सिंह, उप नगर आयुक्त डॉ. मणि भूषण तिवारी, सहायक नगर आयुक्त सुरेंद्र सिंह, सभी जोनल अधिकारी, व्यापारी नेता संजय सिंघानिया, अनूप किशोर अग्रवाल, कमलेश अग्रवाल, मनीष चांदवासिया, गोपाल जायसवाल, राजेश नेमानी, संजय सिंघानिया, राजीव रस्तोगी, संतोष अग्रवाल, नितिन जायसवाल, उमेश मद्धेशिया, सत्य प्रकाश सिंह मुन्ना, रमेश गुप्ता, योगेंद्र दूबे, बलराम अग्रवाल, राजा त्रिपाठी, संजय जालान, पंकज गोयल, नरेश बजाज, अवधेश समेत 31 से ज्यादा व्यापारिक संगठनों के व्यापारी नेता मौजूद रहे।

गोलघर व्यापार मंडल के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि शंकर श्रीवास्तव ने बताया कि बैठक में जितने व्यापारी बैठे थे, उससे ज्यादा खड़े थे। दूसरे विषय पर बात भी नहीं हो रही थी, इसलिए गोलघर के व्यापारी बैठक से निकल आए।

उधर चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया ने कहा कि महापौर एवं नगर आयुक्त को निगम सभागार में बैठक करानी चाहिए। व्यापारी नेता अभय निषाद, आनंद गुप्ता, मनोज गोयल ने बताया कहा कि तमाम व्यापारी नेताओं को बैठने की जगह तक नहीं मिली। कई व्यापारिक संगठनों का सूची में नाम भी नहीं था, उसके बाद भी बैठक की सूचना पर वे पहुंचे थे।

हजारों लोगों को महामारी एक्ट धारा में दर्ज मुकदमे में मिली बड़ी राहत

संवाददाता–गोरखपुर। महामारी एक्ट के विवेचना को 72 घंटे में निस्तारित करने का अभियान चलाया गया था जिसके बाद इन मुकदमों का पर्चा कार्ट कर विवेचना निस्तारित की गई। ज्यादातर में चार्जशीट लगा दी गई थी। मानिटरिंग सेल के इंस्पेक्टर सुदेश कुमार शर्मा ने बताया कि उनके यहां से सभी केस निस्तारित कर दिया गया है। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान दर्ज हुए महामारी एक्ट सभी मुकदमे वापस हो गए हैं। इन मुकदमों में पुलिस के अलावा प्रशासनिक कर्मी भी वादी थे। सरकार ने जनवरी 2021 में ही मुकदमे वापस लेने का फैसला किया था। अन्य जिलों में एक ही साथ सारे केस वापस ले लिए गए थे। जबकि गोरखपुर में एक–एक फाइल वापस लेने में समय ज्यादा लग गया। फिलहाल केस वापस होने से अब न सिर्फ चरित्र सत्यापन में मुकदमों का दाग धुल जाएगा बल्कि कोर्ट कचहरी के चक्कर से भी मुक्ति मिलेगी। गोरखपुर में महामारी एक्ट यानी 188 के तहत 14452 केस दर्ज किए गए थे। वहीं गोरखपुर जोन में यह आंकड़ा एक लाख तीन हजार से भी ज्यादा का था। इनमें सर्वाधिक मुकदमा व्यापारियों के खिलाफ दर्ज किया गया था। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई थी और बिना अनुमति के दुकान खोलने की मनाही थी।

यही नहीं कुछ दुकानों को तय रोस्टर के हिसाब से खोला जा रहा था। पर कई ऐसे दुकानदार थे जो बिना किसी रोस्टर के ही अपनी दुकान खोल दे रहे थे यही नहीं दुकान खोलने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तथा मास्क लगाने का भी निर्देश था। किसी को अपनी दुकानों पर भीड़ नहीं जमा करनी थी।

इन सब मामलों में जिन लोगों ने उल्लंघन किया उनके खिलाफ पुलिस ने महामारी एक्ट में केस किया था। महामारी एक्ट में केस दर्ज होने से जिले में मुकदमे की संख्या एका–एक बढ़ गई थी। महामारी एक्ट के विवेचना को 72 घंटे में निस्तारित करने का अभियान चलाया गया था जिसके बाद इन मुकदमों का पर्चा कार्ट कर विवेचना निस्तारित की गई। ज्यादातर में चार्जशीट लगा दी गई थी। मानिटरिंग सेल के इंस्पेक्टर सुदेश कुमार शर्मा ने बताया कि उनके यहां से सभी केस निस्तारित कर दिया गया है। महामारी एक्ट के यह मुकदमे जब दर्ज किए गए तब तो किसी को कुछ नहीं पता चला क्योंकि पुलिस ने नाम–पता नोट किया और केस दर्ज कर चार्जशीट लगाकर कोर्ट में भेज दिया। पर जब पासपोर्ट, नौकरी सहित अन्य मामलों में चरित्र सत्यापन की बात आई तब काफी लोगों को पता चला कि उनके खिलाफ तो मुकदमे का दाग है। इस मुकदमे से काफी संख्या में लोगों के पासपोर्ट तक नहीं बन पा रहे थे।

सरकार ने कोरोना काल में लॉकडाउन लगाया था। यह घोषणा महामारी एक्ट यानी एपिडमिक डिजास्टर एक्ट 1897 के तहत की गई थी। इस एक्ट के अनुसार अगर कोई शख्स लॉकडाउन का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कानून का उल्लंघन करने या कानून व्यवस्था को तोड़ने पर दोषी को कम से कम एक महीने की जेल या 200 रुपये जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है।

प्रभारी एसएसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि कोरोना के दौरान महामारी एक्ट में दर्ज मुकदमों का पुलिस के स्तर से निस्तारण कर दिया गया है। महामारी एक्ट से जुड़े मामले में अब किसी के चरित्र सत्यापन में कोई दिक्कत नहीं आएगी।

अतिक्रमित 235 वर्ग मीटर जमीन पर प्राधिकरण ने लिया कब्जा

संवाददाता–गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन के निर्देश पर प्राधिकरण के अधिकारियों कर्मचारियों ने हुमायुपुर में 235 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा लिया। यह जमीन तकरीबन 2 करोड़ से अधिक मूल्य की बताई जा रही है जिस पर चाहरदीवारी और गेट लगा कर कमलेश चौधरी ने कब्जा कर रखा था। हालांकि टीम को मौके पर वे जमीन संबंधी कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह ने बताया कि सदर तहसील में राजस्व ग्राम मोहल्ला हुमायुपुर के अंतर्गत अराजी संख्या 152 में शहरी सीलिंग से अतिरिक्त 234.66 वर्ग मीटर जमीन है। इस जमीन पर कमलेश चौधरी नाम के व्यक्ति ने वर्षो से कब्जा कर चाहरदीवारी का निर्माण कर रखा था। बकायदा जमीन पर अपने नाम का बोर्ड लगा कर गेट भी लगा लिया था। मामला संज्ञान में आने पर प्राधिकरण उपाध्यक्ष के निर्देश पर सहायक अभियंता वीके पाण्डेय और वीके शर्मा ने प्रवर्तन कर्मचारियों के साथ मिल कर पुलिस की मौजूदगी में जमीन पर कब्जा लिया। जमीन पर दावा करने वाला पक्ष कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं कर सका। लिहाजा कब्जा लेने के बाद जमीन सील कर दी गई। बल्कि पेंट से दीवार और गेट पर यह भी लिख दिया गया कि यह जमीन जीडीए है, जिसे सील किया गया है।

यूपी बोर्ड परीक्षार्थियों को सफलता के गुर बताए

संवाददाता–अयोध्या। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाएं 22 फरवरी से शुरू हो रही हैं। परीक्षार्थी विभिन्न विषयों की तैयारी में जुटे हैं। विभाग परीक्षा के आयोजन को लेकर तैयारी कर रहा है। इस बीच लालराम कुमार इंटर कॉलेज पटरंगा में परीक्षा पूर्व तैयारी के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक वीरेश कुमार वर्मा ने परीक्षार्थियों को परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के गुर सिखाए। श्री वर्मा ने बच्चों को सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। परीक्षा में अध्ययन सामग्री को किस तरीके से संगठित किया जाए और किस तरीके से उसका रिवीजन किया जाए। यह भी बताया कि किस तरीके से प्रभावी उत्तर लेखन करना चाहिए जिससे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य केके यादव, शिक्षक रामचन्द्र यादव, प्रज्ञा सिंह और विजय शुक्ल सहित अन्य शिक्षक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे।

लापरवाही करने वाले 74 लाभार्थियों पर होगी कार्रवाई

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर में 46, नगर पंचायत उस्का बाजार में 21 और कपिलवस्तु में सात पात्रों ने पहली और दूसरी किस्त का धन लेने के बावजूद निर्माण अभी तक नहीं शुरू करवाया है। जल्द निर्माण शुरू न कराने वाले 74 लाभार्थियों पर विभागीय कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत पहली और दूसरी किस्त का धन लेने वाले पात्रों ने अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं करवाया है। जिसकी पुष्टि होने पर जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) विभाग सख्त हो गया है। एक सप्ताह के भीतर निर्माण कार्य शुरू नहीं करवाए जाने पर ऐसे लोगों के खिलाफ करवाई किए जाने की चेतावनी भी दी है। हर गरीब को पक्का घर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत पत्रों का चयन कर उन्हें तीन किस्त में ढाई लाख रुपये घर बनाने के लिए दे रही है। नगर पालिका सिद्धार्थनगर, उस्का बाजार व कपिलवस्तु नगर पंचायत में करीब अधिकांश ऐसे पात्र हैं जो पहली और दूसरी किस्त का धन पाने के बावजूद भी अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं करवा पाए हैं। ऐसे पात्रों का विभाग जांच करवाकर उनका नाम नगर पंचायत कार्यालय में चस्पा करवा दिया है। चिन्हित लाभार्थी अगर एक सप्ताह के भीतर निर्माण कार्य आरंभ नहीं करवाएंगे तो उनके खिलाफ विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। डूडा की परियोजना अधिकारी सुनीता सिंह ने बताया कि जो लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रथम व दूसरी किस्त पाने के बाद भी निर्माण कार्य नहीं करवा रहे हैं। एक सप्ताह के भीतर निर्माण शुरू करा दें नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

वेतन न मिलने नाराज कर्मियों ने विद्यालय गेट पर धरना– प्रदर्शन किया

संवाददाता–अयोध्या। अमराई गांव स्थित अटल आवासीय विद्यालय के दर्जनों कर्मचारियों ने बकाया वेतन की मांग को लेकर शनिवार को काम–काज ठप रखा। कर्मियों ने मुख्य द्वार पर धरना– प्रदर्शन कर नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि तीन माह से वेतन व नियुक्ति पत्र न मिलने ने कर्मचारियों ने अपना दर्द बयां किया। आन्दोलित कर्मियों ने कहा कि किसी कर्मचारी को अभी तक सैलरी नहीं मिली है। वेतन न मिलने से कर्मचारियों के हाथ तंग है। घर चलाने के लिए उन्हें कई तरह की दुश्वारियों से दो चार होना पड़ रहा है, लेकिन विद्यालय प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। आन्दोलन की खबर मिलने पर उपश्रमायुक्त प्रतिभा तिवारी मौके पर पहुंची। उन्होंने आंदोलित कर्मचारियों को समझा–बुझाकर धरना स्थगित कराया। उन्होंने कर्मचारियों को तीन दिन में बकाया वेतन का भुगतान कराने का आश्वासन दिया है। धरने में राम प्रसाद, राम नारायण, सुनील सिंह, बृजलाल, रामकुमार, आलोक सिंह, राम पदारथ, अजीत वर्मा, साहबलाल यादव, तिलकराम, राघवेंद्र सिंह शामिल रहे।

श्रीलंका के सांसद ने पत्नी संग किए रामलला के दर्शन, श्रीराम का श्रीलंका से बताया खास नाता

संवाददाता–अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद से ही यहां दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आम लोगों से लेकर राजनीति के अहम चेहरे रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। अन्य देशों के राजनेता भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। श्रीलंका के सांसद लक्ष्मण नमल राजपक्षे अपनी पत्नी के साथ रामलला के दर्शन करने पहुंचें। अपनी राम मंदिर यात्रा पर श्रीलंकाई सांसद नमल राजपक्षे ने कहा कि हमें यहां आकर खुशी हुई है और हम राम मंदिर का आशीर्वाद पाकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। खासकर एक श्रीलंकाई होने के नाते ये काफी महत्वपूर्ण है। रामायण पथ से जुड़े हैं और यहां पले–बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि अत्यंत बौद्ध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि, और हिंदू समुदाय के बहुत करीब होने के कारण, आज यहां आना मेरे और मेरी पत्नी के लिए बहुत सम्मान की बात है और हम यहां आकर धन्य महसूस करते हैं। अपनी राम मंदिर यात्रा पर श्रीलंकाई सांसद नमल राजपक्षे ने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री खुद राममंदिर की प्राण–प्रतिष्ठा में शामिल हुए और राम मंदिर का निर्माण और उद्घाटन किया। हमें विश्वास है कि पुरानी महिमा के साथ अपनी नगरी अयोध्या वापस आ गए हैं। मुझे यकीन है कि दुनिया भर से ऐसे कई भक्त रहे होंगे जो इस स्थान के दर्शन करने और आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्रीलंकाई सांसद नमल राजपक्षे अपनी पत्नी के सार्थ अयोध्या पहुंचे थे। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। इस बीच उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 500 वर्ष बाद भगवान राम लला के भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई है। उन्होंने कहा कि पहले भगवान राम टेंट में विराजमान थे, अब दिव्य और भव्य मंदिर में भगवान विराजमान हैं।

सपा अधिवक्ता सभा के पदाधिकारियों ने संकल्प लिया

संवाददाता–अयोध्या। समाजवादी पार्टी कार्यालय लोहिया भवन गुलाबबाड़ी पर समाजवादी अधिवक्ता सभा के नवनियुक्त पदाधिकारियों को जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव ने मनोनयन पत्र सौंपा। इस मौके पर पदाधिकारियों ने आगामी लोकसभा चुनाव– 2024 में सपा प्रत्याशी को जिताने को संकल्प लिया। रुदौली तहसील के अध्यक्ष अजीमुद्दीन एडवोकेट ने रुदौली तहसील की सपा अधिवक्ता सभा की कमेटी प्रस्तुत की। तहसील सोहावल के अध्यक्ष पद पर एडवोकेट राजकुमार यादव को घोषित किया गया तथा मनोनयन पत्र सौंपा गया। एडवोकेट गरिमा यादव को जिला सचिव घोषित किया गया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव, हामिद जाफर मीसम, अंसार अहमद, जिलाध्यक्ष शावेज जाफरी, जितेंद्र प्रजापति, राकेश कुमार, प्रमोद यादव, रामरतन यादव, ओपी राव, नेहा यादव, निगार फातिमा, अनिल कुमार, जगन्नाथ यादव, योगेंद्र प्रताप यादवव अन्य मौजूद रहे।

दुपट्टे के फंदे से लटकता मिला युवती का शव

संवाददाता–संतकबीरनगर। जिले के कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के नेदुला गांव में शुक्रवार की रात एक छात्रा ने कमरे में दुपट्टे से फांसी लगा ली। इस घटना की जानकारी परिजनों ने कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्मार्टम के लिए भेज दिया।

नेदुला गांव की निवासी अर्चना (18) पुत्री सत्यप्रकाश कक्षा 11 में शहर के एबीआरएल इंटर कालेज में पढ़ती थी। शुक्रवार की रात्रि नौ बजे के बाद वह कमरे में चली गई। कुछ देर तक जब वह जब कमरे से नहीं निकली तो उनके परिजन उसे भोजन करने के लिए बुलाने लगे। लेकिन जब उसने कुछ आवाज नहीं दी तो उनके परिजनों ने कमरे के बाहर से जंगले से झांककर देखा कि बिस्तर अस्त व्यस्त पड़ा था। वहीं कमरे में रखी गई कुर्सी भी गिर गई थी। उसके बाद कमरे में गए तो देखा कि दुपट्टे से वह छत की कुंडी से फांसी पर लटकी थी। परिजनों ने उसे लटका देखकर कर शोर मचाया। कुछ देर बाद उनक लोगों ने घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव को नीचे उतारा। उसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रभारी कोतवाली, खलीलाबाद ब्रजेन्द्र प्रसाद पटेल ने बताया कि युवती का शव लटकने की सूचना मिलने पर पहुंच जांच की गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

भाजपा सरकार में आम जनता त्रस्त –पारसनाथ

संवाददाता–अयोध्या। सपा के जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में आम जनता त्रस्त है। महंगाई चरम पर है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में जो विकास कार्य हुआ उसे जनता आज भी याद कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पीडीए को साथ लेकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। यह बातें जिलाध्यक्ष यादव ने रुदौली विधानसभा के सीवन वाजिदपुर गांव में पीडीए की बैठक में कही।

घर वालों ने मोबाइल फोन छीना तो किशोर ने उठा लिया यह जानलेवा कदम

संवाददाता–गोरखपुर। छात्र ने मोबाइल फोन से नींद की गोली की जानकारी ली। इसके बाद मेलाटोनिन 10 मिलीग्राम की दवा का आर्डर दिया। 15 कैप्सूल के एक पत्ते की कीमत 245 रुपये है। उसने छह पत्ते का आर्डर दिया। आनलाइन मंगाई गई दवा लेकर डिलीवरी ब्वाय ने उसे फोन किया तो उसने गांव के बाहर दवा दी।मोबाइल पर सर्च कर मेडिकल स्टोर से एल्प्राजोलाम 0.5 मिलीग्राम की 30 गोली भी खरीदी। किशोर के मोबाइल चलाने की लत से परेशान परिजन जब उससे मोबाइल छीन लिए तो उसने जानलेवा कदम उठा लिया।पिपराइच थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले कक्षा नौ के छात्र ने नींद की 120 गोली खा ली है। उसने 90 गोली मेलाटोनिन 10 मिलीग्राम की आनलाइन मंगाई और एल्प्रोजोलाम 0.5 मिलीग्राम की 30 गोली पास के मेडिकल स्टोर से खरीदी। दोपहर तक जब वह नहीं उठा तो स्वजन ने जगाने की कोशिश की। बेहोशी की हालत में देख स्वजन उसे लेकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) गोरखपुर पहुंचे। यहां डाक्टरों ने उसे बाल रोग विभाग की आइपीडी में भर्ती किया है। एम्स थाना पुलिस को सूचना दे दी गई है।छात्र महानगर के एक स्कूल में पढ़ता है। स्वजन का कहना है कि देर तक मोबाइल देखने के कारण सभी उससे परेशान रहते थे। इस कारण उसे कई बार फटकार भी मिलती थी। उसका मोबाइल फोन छीनकर रख लिया जाता था। इससे वह नाराज रहता था।छात्र के दोस्तों का कहना है कि कुछ दिनों से वह नींद न आने की शिकायत करता था। कहता था कि रात में उसे नींद नहीं आती है। इस कारण परेशान रहता था। छात्र ने मोबाइल फोन से नींद की गोली की जानकारी ली। इसके बाद मेलाटोनिन 10 मिलीग्राम की दवा का आर्डर दिया। 15 कैप्सूल के एक पत्ते की कीमत 245 रुपये है। उसने छह पत्ते का आर्डर दिया। आनलाइन मंगाई गई दवा लेकर डिलीवरी ब्वाय ने उसे फोन किया तो उसने गांव के बाहर दवा दी।मोबाइल पर सर्च कर मेडिकल स्टोर से एल्प्राजोलाम 0.5 मिलीग्राम की 30 गोली भी खरीदी। नारकोटिक्स ग्रुप का होने के कारण यह दवा सिर्फ डाक्टर के पर्चे पर ही बेची जाती है, लेकिन मेडिकल स्टोर से उसे आसानी से दवा मिल गई। डाक्टरों का कहना है कि दोनों दवाएं बच्चों को नहीं दी जाती हैं। दवा निकालने के लिए नाक में पाइप डाला गया है।बिना डाक्टर का पर्चा एल्प्राजोलाम की गोली देने का मामला गंभीर है। यह भी ड्रग विभाग की लापरवाही जता रही है।

नगर आयुक्त को माया बाजार में ब्लाक मिली नाली, तोड़ने के निर्देश

संवाददाता–गोरखपुर। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल शनिवार की सुबह मार्निंग वॉक पर साइकिल से निकलते तो लगे हाथ माया बाजार का निरीक्षण भी कर डाला। माया बाजार वार्ड संख्या 62 के पार्षद शमद गुफरान के साथ वार्ड की एक–एक गली का भ्रमण किया। हठ्ठी माता मंदिर से घोष कंपनी जाने वाले मार्ग पर एक मकान के पास नाली पूरी तरह बंद किए जाने का कड़ा संज्ञान लिया और तोड़ने के निर्देश दिए।

मौके पर मौजूद सुपरवाइजर को फटकार लगाई और बोला कि नालियों का बहाव कही रुकना नहीं चाहिए। माया बाजार के हरिजन बस्ती, यादव टोला जुबली रोड समेत विभिन्न मोहल्ले का निरीक्षण करके डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए लोगों को जागरूक किया। लोगों से बातचीत कर साफ सफाई पर फीडबैक भी लिया। कहा कि सड़क पर कूड़ा फेंकते मिलने पर जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसलिए कूड़ा कलेक्शन करने वाली गाड़ियों को ही कूड़ा दे। बदले में निर्धारित यूजर चार्ज भी समय पर दें। हाल ही भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले शमद गुफरान ने नगर आयुक्त से वार्ड में विभिन्न स्थानों पर सीवर लाइन डालने की मांग की।

नाम परिवर्तन की सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी चन्द्रेश्वर प्रताप सिंह पुत्र श्री कृष्णचन्द्र सिंह ग्राम संसारपुर फुटहिया पोस्ट– गांधीनगर जनपद बस्ती (उ.प्र.) का निवासी है। मेरी पुत्री कौस्तुकि सिंह (KAUSTUKI SINGH) सेन्ट वेसिल स्कूल में कक्षा 5 में अध्ययनरत है। विद्यालय के अभिलेखों में मेरी पुत्री का नाम अनुवाईसी सिंह (ANUWAISHI SINGH) हो गया है इसके स्थान पर विद्यालय के अभिलेखों में पुत्री का नाम कौस्तुकि सिंह (KAUSTUKI SINGH) पुत्री चन्द्रेश्वर प्रताप सिंह प्रताप सिंह माता श्रीमती प्रीती सिंह किया जाना आवश्यक है।

दैनिक भारतीय बस्ती

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक दिनेश चन्द्र पाण्डेय

प्रबन्ध सम्पादक–दिनेश सिंह

संयुक्त सम्पादक–प्रदीप चन्द्र पाण्डेय

अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय– चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद

लखनऊ कार्यालय– आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।

गोरखपुर कार्यालय– इलाहीबाग गोरखपुर।

मो09450567450 9336715406, ई.मेलbhartiyabasti@yahoo.com bhartiyabasti@gmail.com